● वर्ष-3
● अंक-123
रायपुर, रविवार
31 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पुष्पा 2, फ़ाइटर जैसी बड़ी फ़िल्में...

कश्मीरी पंडितों पर कम कहा गया- जस्टिस कौल

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बात की। उन्होंने कहा कि घाटी में अलगाववादी उग्रवाद के आगमन के साथ ही विस्थापित हुए साढ़े चार लाख कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत कम कहा गया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे इतने बड़े मतदाता नहीं थे कि राजनीतिक दखल के लिए आमंत्रित कर सकें।

न्यायमूर्ति कौल पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 1980 के दशक से राज्य और गैर राज्य तत्वों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए एक निष्पक्ष सत्य और सुलह आयोग को गठित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से शांति भंग होने से पहले विभिन्न समुदायों के लोग एकता में रहते थे और वे यह समझने में असमर्थ हैं कि स्थिति धीरे-धीरे कैसे खराब हो गई।

कौल खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। उनका मानना है कि तीस साल से ज्यादा समय की बेलगाम हिंसा के बाद अब लोगों के लिए आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। न्यायमूर्ति कौल ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में भारत मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के उस सर्वसम्मत फैसले के बारे में बात की, जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था।

उन्होंने कहा, यह सर्वसम्मत फैसला था। जिसका मतलब है कि मह सभी ने

सोचा होगा कि यह सही रास्ता है। निसंदेह प्रत्येक फैसला, खासतौर पर महत्वपूर्ण निर्ण वाद-विवाद पैदा करेगा। ऐसे लोग होंगे जो इसके खिलाफ अपना नजरिया सामने रखेंगे। यह वास्तव में मुझे प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि यह फैसले पर एक राय है और हमें इसके बारे में अति-संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

उन्होंने मुस्लिम बहुल राज्य में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के विस्थापन पर चुप्पी पर अफसोस जताया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, %इससे पहले सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तव में कोई समस्या नहीं थीं। लेकिन फिर पतन एक ऐसे चरण में पहुंच गया, जहां अपने ही देश के एक समुदाय के साढ़े चार लाख से ज्यादा लोग अपने स्थान से विस्थापित हो गए। मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कम कहा गया था। उन्होंने कहा,शायद वे मतदाता इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे कि राजनीतिक दखल को आमंत्रित कर सकते थे। फिर स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि सेना को बुलाना पड़ा, क्योंकि देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ रही थी।

सत्य और सुलह आयोग गठित करने की सिफारिश के बारे में पूछे जाने पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह स्वीकार करने का %अच्छा तरीका% है कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने कहा, %सवाल यह है कि क्या हम इस मुद्दे से नहीं निपटते? क्या हम उस चीज को अभी भी लोगों को चोट पहुंचाने दें जहां यह दर्द होता है? मैंने सोचा कि यह स्वीकार करने का एक अच्छा तरीका था कि कुछ गलत हुआ है और वह गलत क्या था जो हुआ है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए।

30 साल एक लंबा समय है। आपको आगे बढ़ना होगा। पूर्व न्यायाधीश कौल ने कहा है कि वायु प्रदूषण के मुद्दे को कभी-कभी %राजनीतिक% मुद्दे के तौर पर लिया जाता है। लेकिन अदालतों को कार्यपालिका का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वायु प्रदूषण से जुड़ा आदेश पारित करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा कई कदम उठाए गए थे।

सेवानिवृत्ति के बाद सरकार पद संभालने को लेकर कही ये बात

पूर्व न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद संभालने को लेकर बंटी राय के बीच उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौल ने अपना विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस तरह के रोजगार की पेशकश की जाती है, उन्हें फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने शुक्रवार ने कहा, यह संवैधानिक अदालत के न्यायाधीश पर छोड़ दें कि वह क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दो तरह के पद हैं। एक न्यायाधिकरण हैं, जहां किसी को न्यायाधिकरणों का संचालन करना पड़ता है। लोग इस तरह के काम स्वीकार करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह इसी तरह का काम है।%न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सितंबर 2023 में उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले दो साल की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की मांग की गई थी। पीठ ने कहा था कि यह शीर्ष अदालत का काम नहीं है कि वह किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद की पेशकश स्वीकार करने से रोके या संसद को इस संबंध में एक विशिष्ट कानून बनाने का निर्देश दे।

श्रीराम के ननिहाल से शगुन के चावल और ससुराल से जल

अयोध्या। जैसे-जैसे अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ का दिन नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या धाम में उत्साह और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि अयोध्या में भगवान राम से अपना नाता रखने वाले देश और दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग तमाम तरह के उपहारों को भेजने की शुरुआत भी कर चुके हैं। शनिवार को जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का शुभारंभ कर रहे थे, तो नेपाल के जनकपुरी से चार हजार लीटर जल लेकर लोग पहुंचे। यही नहीं छत्तीसगढ़ से भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी से शगुन के चावल भी भेजे गए। जानकारी के मुताबिक भगवान राम की ससुराल जनकपुरी से लेकर उनके ननिहाल और उनके वंशजों की ओर से कई तरह के उपहार की सूची तैयार कर अयोध्या धाम भेजे जाने की शुरुआत कर दी गई है।

अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ तो 22 जनवरी को होना है, लेकिन उसकी भव्य तैयारियां अयोध्या में लगातार जारी है। इन्हीं तैयारी की कड़ी में देश और

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से अयोध्या में भगवान राम और माता जानकी के लिए उपहार की झड़ी लग रही है। शनिवार को नेपाल के जलकलैया बारा से आए कुणाल और उदघोष ने अमर उजाला डॉट कॉम को बताया कि वह नेपाल की सात बड़ी नदियों के जल से प्रवाहित होने वाली सप्तकोशी नदी का चार हजार लीटर जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। वह कहते हैं कि इस जल में तमाकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी, भोटेकोशी, तमूरकोशी, इंद्रावती और सुनकोशी नदियों का जल शामिल है। कुणाल कहते हैं कि अभी इन पवित्र नदियों के जल के बाद माता जानकी के लिए उनके मायके जनकपुरी से वस्त्र आभूषण, मिठाई और ग्यारह तरह के पकवान भेजे जाएंगे। जनकपुरी के माता जानकी मंदिर से जलकलैया बारा आश्रम के सन्यासी और माता जानकी के वंशज 20 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे।

इसके अलावा प्रभु श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के चंदखुरी से शगुन के चावल भी अयोध्या भेजे जा रहे हैं। ननिहाल छत्तीसगढ़ से आने वाले चावल और ससुराल नेपाल से आने वाले मेवों से भरे थाल का विशेष भोग तैयार किया जाना है। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रभाकर दास बताते हैं कि उनकी एसोसिएशन की ओर से भी इस प्रसाद के लिए योगदान दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले का थोड़ा-थोड़ा चावल भी शामिल है।

पीएम मोदी को अपने घर पाकर मीरा के परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पीएम ने मीरा की बनाई चाय पी और कहा चाय मीठी कर दी... मैं भी चाय बनाता था।

नए साल में बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार के नियम बदलेंगे

नई दिल्ली। वर्ष 2023 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

बैंक लॉकर समझौते- बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए, एक महत्वपूर्ण समय सीमा है- 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लॉकर एक जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं।

बीमा पॉलिसी- भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसीधारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है।

बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट= नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए, यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करना- एक जनवरी से जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प नहीं होगा।

प्रमुख समाचार

राजीव ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को किया खारिज, कहा- आधे-अधूरे तथ्य पर आधारित

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत सरकार द्वारा एप्पल को कथित तौर पर निशाना बनाने के संबंध में द वाशिंगटन पोस्ट में किए गए दावों का खंडन किया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संभावित सरकारी हैकिंग प्रयासों के बारे में ऐप्पल की चेतावनी के बाद सरकार ने स्वतंत्र भारतीय पत्रकारों और विपक्षी दल के राजनेताओं के आईफोन से समझौता करने की मांग की थी। चन्द्रशेखर ने रिपोर्ट को आधे तथ्य, पूरी तरह से अलंकृत जानकारी बताते हुए खारिज कर दिया और इसे भयानक करार दिया। इसे अपने सोशल मीडिया एक्स पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा वॉशिंगटन पोस्ट की भयानक कहानी का खंडन करना थकाऊ है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा। यह कहानी आधे-अधूरे तथ्य और पूरी तरह से अलंकृत है। 27 दिसंबर को एमनेस्टी के सहयोग से प्रकाशित एक कहानी में पोस्ट ने बताया था कि कुछ पत्रकारों को उनके आईफ़ोन पर स्पाइवेयर से निशाना बनाया गया था।

भजन लाल की कैबिनेट में खिलाड़ी, पुजारी से लेकर प्रोफेसर तक, 40 के सुरेश सबसे युवा मंत्री

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट का गठन हो गया है। 3 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के 27 दिन बाद आखिरकार राजस्थान में सरकार ने पूरा स्वरूप ले लिया। भजनलाल सरकार के 22 मंत्रियों ने शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। इस तरह से 15 नेताओं ने कैबिनेट, पांच ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पांच ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की नई कैबिनेट की औसत उम्र 55 साल छह महीने है। 40 साल के सुरेश सिंह कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री हैं। वहीं 72 साल के करोड़ी लाल मीणा कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। छह मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। 12 मंत्रियों की उम्र 51 से 59 साल के बीच है। वहीं, सात मंत्री ऐसे हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है।

विनेश ने कर्तव्य पथ पर छोड़ा खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार, बजरंग ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस कर दिया है। उन्होंने 26 नवंबर को पुरस्कारों को लौटाने का एलान किया था। शनिवार (30 दिसंबर) को विनेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कर्तव्य पथ पर खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को रख दिया। इसे बाद में पुलिस ने उठा लिया। पहलवान बजरंग पूनिया ने इस पूरे वाकये का वीडियो शेयर किया है। बजरंग पूनिया ने एक्स (पहले ट्विटर) लिखा, यह दिन किसी खिलाड़ी के जीवन में न आए। देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। विनेश और उनके साथी प्रधानमंत्री कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद विनेश ने कर्तव्य पथ पर अपने पुरस्कारों को रख दिया। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद साक्षी मलिक ने यह कहते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया कि फिर से बृजभूषण जैसा ही चुना गया है तो क्या करें?

केरल सरकार ने सुको में दाखिल की संशोधित याचिका

नई दिल्ली। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर कर राज्यपाल को लंबित बिलों को तुरंत मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की है। संशोधित याचिका में, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उन शर्तों पर दिशानिर्देश देने की मांग की है जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं, उनकी सहमति रोक सकते हैं या उन्हें राज्य विधानसभा को वापस कर सकते हैं। यह संशोधन पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका में किया गया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को प्रस्तुत बिलों के निपटान के लिए लागू समयसीमा पर संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान में जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश की व्याख्या करने की मांग की है। राज्य ने याचिका में इस बात पर जोर दिया कि यह घोषित किया जाना चाहिए कि राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि राज्यपाल को लंबित विधेयकों के निपटारे के लिए तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

बंदरगाह पर गश्त के लिए फास्ट इंटरसेप्टर बोट तैनात, राहत और बचाव अभियानों में आएगी तेजी

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार पुलिस ने चौबीस घंटे बंदरगाह पर गश्त के लिए पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में एक अत्याधुनिक फास्ट इंटरसेप्टर बोट (एफआईबी) तैनात की है। इसा इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने और अवैध रूप से मछली पकड़ने के काम को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, यह तेजी से राहत व बचाव कार्य चलाने के भी काम आएगी। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जेट्टी (समुद्र तट के जल में बनी पत्थर की दीवार या ढांचा, जिससे नावों को बांधते हैं और जहां लोग चढ़ते-उतरते हैं) तक सीमित है और नौसेना व तटरक्षक बल मुख्य रूप से पांच समुद्री मील से ज्यादा दूरी पर गश्त करते हैं। जिससे बंदरगाह क्षेत्र में शून्यता पैदा हो जाती है। इसलिए कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत महसूस की गई थी। अंडमान और निकोबार पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने काफी विचार-विमर्श के बाद पोर्ट ब्लेयर में एफआईबी को तैनात करने का फैसला लिया।

कश्मीर पर लिखी जा चुकी है नई कहानी

हर्ष वी पंत

संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त करने की अगस्त 2019 में शुरू हुई प्रक्रिया तब पूरी हुई, जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी। 5 अगस्त 2019 को, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा की थी, जिसने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) से छूट देते हुए उसे अपना संविधान बनाने की इजाजत दी थी। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया- बिना विधानमंडल वाला लद्दाख और विधानमंडल वाला जम्मू-कश्मीर।

यह कायापलट कर देने वाला कदम था और स्वाभाविक ही इससे पक्ष-विपक्ष में तीखी प्रतिक्रिया हुई, जो अदालत तक पहुंची। इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली करीब 23 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना केंद्र के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण की प्रक्रिया की तार्किक परिणति था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अनुच्छेद को निष्क्रिय घोषित करने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 25 नवंबर, 1949 को जब राज्य के लिए एक उद्घोषणा जारी की गई, तो राज्य ने अपनी संप्रभुता 'पूर्ण रूप से और अंतिम तौर पर' समर्पित कर दी थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।

फैसले के बावजूद इस मसले पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रेखा जरूर खींच दी है। यह फैसला वैश्विक मंच पर एक ऐसे नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत करता है, जो भारत की घरेलू समस्याओं का निर्णायक समाधान खोजने को लेकर गंभीर हैं। कश्मीर पर यथास्थिति बहुत पहले ही डगमगा चुकी थी। यह केवल राजनीतिक और नीतिगत जड़ता ही थी, जो भारतीय नीति-निर्माताओं को इसे चुनौती देने से रोक रही थी। कथित कश्मीर समस्या हमेशा से राज्य के लोगों और देश के बाकी हिस्से के बीच एक द्विपक्षीय मसला रही है। शेष भारत एक तरह के कानूनों से शासित होता रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर के पिछले करीब सात दशकों से अपने अलग कानून रहे हैं। जैसे जम्मू-कश्मीर के लोगों का शेष भारत में काफी कुछ दांव पर है, वैसे ही शेष भारत भी जम्मू-कश्मीर को लेकर खासा संवेदनशील है। मोदी सरकार ने रेखांकित किया कि वह न केवल भारत की कमजोर सीमाओं को मजबूत करने को लेकर गंभीर है, बल्कि एक ऐसे राज्य की आकांक्षाओं से भी परिचित है, जो अपने संसाधनों के बावजूद हिंसा और पतनशील राजनीति का गढ़ बन गया है।

सरकार के सुधार अजेंडे की सफलता जम्मू-कश्मीर के लोगों के ही लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर पूर्ण अमल में समय लगेगा लेकिन हिंसा में कमी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और पर्यटकों की बढ़ती संख्या जैसे नतीजे अभी से दिखाई देने लगे हैं। इन सरकारी कदमों की आलोचना भी हो रही है, लेकिन इनके पीछे जो मकसद हैं उनकी गंभीरता की पुष्टि भारत विरोधी तत्वों की गतिविधियों से होती है। आखिर लद्दाख में चीन की बढ़ी हुई आक्रामकता का मुख्य कारण यही तो था कि ये कदम चीन के मुकाबले भारत की रणनीतिक स्थिति को स्थायी तौर पर मजबूती दे सकते हैं। भारत आखिरकार अपना इरादा स्पष्ट कर रहा है और इससे उन लोगों का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है जो यथास्थिति के साथ सहज रिश्ता बना चुके थे। सुप्रीम

कोर्ट के फैसले के बाद कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया है। पाकिस्तानी राजनेता जो भी बयानबाजी करें, वह सब उनकी घरेलू राजनीति के लिए है। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के अगस्त 2019 के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करने और अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने जैसे फैसलों का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। इन फैसलों का कोई असर नहीं हुआ सिवाय इसके कि इनसे पाकिस्तान की निरर्थकता और ज्यादा स्पष्ट हो गई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर पाकिस्तान बदले हालात की हकीकत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है तो एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी चुनाव तक इंतजार करना होगा। आगे जो भी हो, इतना निश्चित है कि वह भारत की शर्तों पर ही होगा। बाकी दुनिया की जहां तक बात है तो एक उभरते आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति के तौर पर भारत के साथ उसका जुड़ाव पहले ही शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस भावना को और मजबूत करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के व्यापक मूड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। यह भी साफ हो चुका है कि अब भारत या मोदी सरकार को कश्मीर मुद्दे के लेंस से देखना संभव नहीं रहा। अनुच्छेद 370 को खत्म करके मोदी सरकार ने वैश्विक मंच पर भारतीय विदेश नीति के समक्ष पिछले सात दशकों से मौजूद एक गंभीर चुनौती को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मोदी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था।

नक्सलियों के डीएकेएमएस उपाध्यक्ष के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आसूचना पर चिंतलनार से 223 वाहिनी सीआरपीएफ का बल एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी आरएसओ/एरिया डोमिनेशन हेतु ग्राम लखापाल, रावगुड़ा जंगल की ओर रवाना हुये थे। अभियान के दौरान मल्लेवागू नाला के पास से नक्सलियों के डीएकेएमएस उपाध्यक्ष कुहराम देवा पिता गंगा उम्र लगभग निवासी लखापाल एवं नक्सली मिलिशिया सदस्य बारसे बण्डी पिता माडका निवासी रावगुड़ा को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार दोनो नक्सलियों के रिकार्ड की जांच करने पर कुहराम देवा थाना चिंतलनार क्षेत्रान्तर्गत 6 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में मतदान दल के सुरक्षा बलों पर जान से मारने की नीयत से आईईडी विस्फोट कर फायरिंग करने की घटना में अन्य नक्सली सदस्यों के साथ सम्मिलित था। घटना के संबंध में थाना चिंतलनार में अपराध क्रमांक 06/2023 धारा 147, 148, 149, 120 (ची) 307 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है। वहीं बारसे बण्डी थाना चिंतलनार क्षेत्रान्तर्गत 11 जून 2018 को मल्लेवागू नाला के पास सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट करने की घटना में अन्य नक्सलियों के साथ सम्मिलित था। उक्त घटना के संबंध में थाना चिंतलनार में अपराध क्रमांक 06/18 धारा 120 (बी) भादवि., 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण में न्यायालय सुकमा द्वारा बारसे बण्डी की गिरफ्तारी हेतु पूर्व से स्थायी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तार दोनो नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

हत्या की वारदात में शामिल एक लाख का ईनाम नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी व बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम जांगला थाना क्षेत्र के पोटेनार व तुंगाली की नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी। इस दौरान पोटेनार के जंगल पगडंडी रास्ते में नक्सलियों द्वारा प्रेशर आईईडी लगाया गया था। जिसके विस्फोट से डीआरजी के एक जवान के पैर में चोट आई। विस्फोट के बाद भाग रहे एक नक्सली को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम डीएकेएमएस अध्यक्ष महादेव करटाम निवासी पिटेतुंगाली होना बताया। गिरफ्तार नक्सली 30 सितंबर 2020 को जांगला क्षेत्र के बरदेला के वार्ड पंच व भूतपूर्व धनीराम की हत्या की घटना में शामिल था। वह डीएकेएमएस अध्यक्ष के पद पर सक्रिय है। जिस पर छग शासन की ईनाम नीति के तहत 1 लाख का ईनाम घोषित हैं। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ जांगला थाना में 2 स्थाई वारंट लंबित हैं। उक्त नक्सली के विरुद्ध जांगला थाना में वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया।

महादेव सट्टा ऐप: आरक्षक भीम सिंह की पत्नी को ईडी का नोटिस

अकाउंट में बड़े ट्रांजेक्शन होने की मिली जानकारी

दुर्ग। दुर्ग में महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार आरक्षक भीम सिंह यादव की पत्नी को ईडी ने नोटिस जारी किया है। भीम यादव के घर पर सीमा यादव के नाम पर नोटिस चस्पा कर उसे कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

ईडी की टीम 28 दिसंबर को आरक्षक भीम यादव के घर पहुंची जहां घर में ताला लगा हुआ था जिसके बाद ईडी ने घर पर नोटिस चस्पा कर वापस लौट गई। नोटिस में आरक्षक भीम यादव की पत्नी सीमा यादव के नाम समन चस्पा किया है और पूछताछ के लिए आरक्षक की पत्नी को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। इस नोटिस में सीमा यादव को 28 दिसंबर 2023 को दोपहर 12.30 बजे रायपुर कार्यालय में पेश होने के लिए लिखा था जबकि नोटिस चस्पा करने का दिन भी 28 दिसंबर का था, जानकारी के मुताबिक सीमा यादव के खाते में कई बड़े ट्रांजेक्शन किए गए हैं।

आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी के अफसरों ने रायपुर और भिलाई से लगभग सात करोड़ रुपये के साथ असीम दास उर्फ बप्पा और आरक्षक भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। ईडी ने बीते तीन नवंबर को भिलाई के हाउसिंग बोर्ड निवासी असीम दास उर्फ बप्पा के घर और रायपुर स्थित होटल से लगभग सात करोड़ रुपये नगद जब्त किये थे। इस दौरान 15 करोड़ से अधिक के ऑनलाइन अकाउंट सीज किए गए थे।

ईडी ने आरक्षक भीम यादव और असीम बप्पा को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में अजय सिंह राजपूत की बेंच में पेश किया। आरक्षक और असीम दास अभी भी न्यायिक हिरासत में है। आरक्षक भीम सिंह यादव और उसके दोनों भाई आरक्षक नकुल यादव और सहदेव यादव शुरुआत से ही ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त हैं। इसकी वजह से इन तीनों ने बड़े पैमाने पर काला धन अर्जित किया है। ईडी ने जब आरक्षक भीम सिंह का बैंक अकाउंट खंगाला तो पत्नी सीमा यादव के बैंक खाते में भी बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन होना पाया गया। इसी वजह से ईडी ने भीम की पत्नी सीमा यादव को समन भेजकर कार्यालय में पेश होने को कहा है।

पीडीएस में 12 दुकान संचालकों ने की हेराफेरी

■ **खाद्य विभाग ने 5 दुकानों को किया निरस्त, 9 से हुई चावल की रिकवरी**

महासमुंद। गरीबों को मुफ्त और कम दामों में राशन मुहैया कराने के लिए शासन शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित करती है। लेकिन दुकान संचालक ही अगर गरीबों के राशन पर डाका मार दे तो बेचारे गरीब कहां जाये ये एक बड़ा सवाल है। एक ऐसा ही मामला महासमुंद जिले का है, जिसपर खाद्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सुस्त नजर आ रहा है। हेराफेरी करने वाले 12 दुकान संचालकों में से अब तक 9 पर कार्रवाई की गई है।

दरअसल महासमुंद में पीडीएस के तहत हेराफेरी की आंशका को देखते हुए सितंबर 2022 में जिला खाद्य अधिकारी को जांच के लिए शासन से एक पत्र आया। इस आधार पर पीडीएस की दुकानों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि जिले के 591 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में से 12 (बागबाहरा में कसीबाहरा, पिथौरा मे सागुनडाप, बसना के सूखापाली, बिरसींगपाली, बसना, कुडेकेल, सरायपाली के पसरापाली, केना, कोदोकुडा, खैरझिटी, सल्डीह , अंतरला) शासकीय उचित मूल्य की दुकानो से चावल 1946.04 क्विंटल, शक्कर 45.35 क्विंटल, नमक 69.5 क्विंटल, चना 4.56 क्विंटल का गबन किया गया है। उसके बाद खाद्य विभाग के आला अधिकारी ने सभी दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है पर विडंबना देखिये कि 14-15 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक राशन गबन करने वालों से सौ फीसदी न तो चावल वसूला गया और न ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा गया।

इन 12 दुकान संचालकों में 9 से 772.92 क्विंटल चावल रिकवर किया गया। लेकिन 3 दुकान संचालकों से आज तक 1173.12 क्विंटल चावल वसूली करना बाकी है। इस पूरे मामले में खाद्य अधिकारी का कहना है कि 12 में से 05 दुकानों को एसडीएम ने निरस्त कर दिया है।

बकाया बोनस की राशि लेने बैंकों में लगी लंबी कतार

9 साल बाद पैसे मिलने से किसानों में खुशी

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 साल के धान की बकाया बोनस की राशि 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर किसानों के खातों में डाल दी। इसके तहत खैरागढ़ जिले में लगभग 45 हजार किसानों के खाते में लगभग 70 करोड़ 1 लाख 25 हजार पहुंचे हैं।

वहीं, खातों में पैसा आने के बाद से ही लगातार किसान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखाओं का रुख कर रहे हैं। 25 दिसंबर से लगातार बैंकों की शाखाओं में किसानों की लंबी-लंबी कतारे भी देखने को मिल रही है। लगभग 9 साल बाद मिले धान के बकाया बोनस राशि से किसान खुश नजर आ रहे हैं। वहीं, बैंक की ओर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे किसानों के लिए छाव की व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही किसानों के खाते में दो साल का बोनस दिया जाएगा। सत्ता में काबिज होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने 18 लाख लोगों को पीएम आवास के लिए मंजूरी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि 25 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। फिर सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को राज्य के किसानों को खरीफ विपणन साल 2014-15 और साल 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया गया। धान उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना के लिए राशि का प्रावधान भी किया है।

गरियाबंद में 11 शिक्षाकर्मियों को 3-3 साल की कड़ी सजा

गरियाबंद। साल 2008-09 की बात है। मैनपुर जनपद में शिक्षाकर्मी के पद पर कई शिक्षकों की भर्ती हुई। इसके कुछ दिनों बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए शिक्षाकर्मी की नौकरी हासिल की है। जिसके बाद प्रार्थी कृष्ण कुमार ने मैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि 2008-09 में शिक्षाकर्मी चयन के दौरान हुए कुछ शिक्षा कर्मियों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी हासिल की है। इन अभ्यर्थियों ने बीएड और डीएड का फर्जी प्रमाण बनवाया और भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद इन प्रमाणपत्रों को दिखाया।

मैनपुर थाने से मामला गरियाबंद जिला एवं अपर सत्र न्यायालय पहुंचा। कोर्ट ने जांच में शिकायत सही पाई। इस दौरान पूरे मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आरोप लगे। जिसके बाद कोर्ट ने 11 शिक्षाकर्मियों को 3-3 साल की कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिन शिक्षाकर्मियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनमें दो महिलाएं भी है। अरविंद सिन्हा, संजय शर्मा, शंकर लाल साहू, भेगेश्वरी साहू, देवनारायण साहू, दौलत राम साहू, ममता सिन्हा, हेमलाल यादव, पीतांबर राम साहू, शिवकुमार साहू, योगेंद्र कुमार सिन्हा है। इन सभी को कोर्ट ने तीन साल कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ईमानदारी और मेहनत साहू समाज की ताकत : साव

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज सिम्स ऑडिटोरियम में साहू समाज की विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने भक्त माता कर्मा की आरती और पूजा अर्चना के साथ सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन में बिलासपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में युवक युवतियां अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया। बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला भी इस अवसर पर मौजूद थे। अरुण साव के राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में महती जवाबदारी मिलने पर उनका जिला साहू समाज की ओर से सम्मान किया गया। श्री साव ने सम्मान से अभिभूत होकर अपने संबोधन में कहा की मेहनत और ईमानदारी साहू समाज की पहचान है। जिसके कारण समाज आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ये विशेषता समाज में आगे भी बने रहना चाहिए। इसके साथ ही अन्य समाजों को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता साहू समाज में निहित है। राज्य की तरक्की और बेहतरी के लिए ये गुण जरूरी है।

चूल्हे के धुंए से मिली मुक्ति झटपट बन जाता है खाना

कांकेर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने श्रीमती यमुना उइके की चूल्हे से लकड़ी जलाकर खाना बनाने से मुक्ति दिला दी। उन्होंने कहा कि निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा शासन ने उपलब्ध कराया है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दे रही है। लाभान्वित हितग्राही श्रीमती यमुना उइके उत्तर बस्तर कांकेर के ग्राम किरगोली निवासी हैं। श्रीमती यमुना ने बताया कि पहले चूल्हा में खाना बनाना पड़ता था। पूरा किचन धुएं से भर जाता था। इसके कारण आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में भी बड़ी समस्या होती थी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन मिला है तब से खाना बनाने में बहुत सुविधा होती है। अब समय की भी बचत होती है और रसोई घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। उन्होंने कहा कि गैस चूल्हा में खाने बनाने से पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है।

यात्री बस का हुआ ब्रेक फेल, 3 यात्री घायल

सुकमा। तोंगपाल थाना क्षेत्र अंर्तगत कोयलाभट्टी के नजदीक रायपुर से सुकमा जा रही तेज रफ्तार यात्री बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस अनियंत्रित होकर नाली में घुस गई। हादसे में 3 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यदि बस नाली में नहीं घुसती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पायल ट्रेवल्स की यात्री बस रायपुर से सुकमा के लिए निकली थी। जगदलपुर के बाद सुकमा के रास्ते में तोंगपाल के कोयलाभट्टी के नजदीक बस का ब्रेक फेल हो गया, इससे बस अनियंत्रित हो गई। जिसके बाद बस सड़क किनारे नाली में जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों को चोट आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जिन यात्रियों को चोट आई है, उन्हें फौरन तोंगपाल के अस्पताल ले जाया गया। अन्य यात्रियों को किसी दूसरे माध्यम से सुकमा जिला मुख्यालय तक लाया गया।

लापरवाह और परेशान करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

बलौदाबाजार। नवनियुक्त खेलकूद एवं युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया गया। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से प्रेसवार्ता कर शासन और उनकी ओर से किये जाने वाले प्राथमिकता पूर्ण कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने साफ शब्दों में अवैध शराब और संलिप्त शराब कोचियों को लेकर चेतावनी दी और कहा कि अवैध शराब, जुए सट्टे का कारोबार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। समाज सुरक्षित रहे, माता बहने सुरक्षित रहे मेरा पहला कर्तव्य है। इसके साथ ही ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उभारा जाएगा, जो कमी होगी उसे दूर करेंगे। राजस्व विभाग के कामकाज को लेकर कहा कि, अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे और गलत कार्य या किसानों को परेशान करने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी।

बलरामपुर पहुंचा अयोध्या राम मंदिर का अक्षत कलश

बलरामपुर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का अक्षत कलश शनिवार को बलरामपुर पहुंचा। बलरामपुर के रामानुजगंज में महिलाओं ने शोभायात्रा निकाल अक्षत कलश का भव्य स्वागत किया। छोटे बच्चे और पुरुष भी शोभायात्रा में शामिल हुए। सभी भक्ति गीत पर नाचते गाते नजर आए। लोगों में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले राम मंदिर का अक्षत कलश पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है। इस कलश के माध्यम से लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अक्षत कलश रामानुजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा तो लोग काफी उत्साहित नजर आए। केरवाशीला, आरागाही सहित कई गांवों में अक्षत कलश के साथ शोभायात्रा निकाली गई। केरवाशीला, कमलपुर और आरागाही में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचने के बाद यहां के ग्रामीण आस्था और भक्ति में लीन होकर भजन-कीर्तन और नृत्य करते हुए पूरे गांव में फेरी निकाले।

पोषण राशि में फूड इंस्पेक्टर का सेंधमारी, कार्रवाई के संकेत

बीजापुर। बीजापुर जिले में संचालित 180 राशन दुकानों के बैंक खातों में पंचम वित्तीय पोषण राशि वितरण में गड़बड़ी संबंधी शिकायत को प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर बीजापुर राजेंद्र कटारा के आदेश पर डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी की अध्यक्षता में महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केंद्र बीजापुर अजीत सुंदर, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम जीएस कश्यप द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। तीन सदस्यीय जांच दल ने शुरूआती जांच में वित्तीय पोषण प्रदाय संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन करने के साथ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे को तलब किया है।

कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि शिकायत को तत्काल

संज्ञान में लेते हुए अविलंब जांच के आदेश दिए गए हैं। दल को जांच जल्द पूरी कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया है। बहरहाल मामला उजागर होने के बाद से खाद्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जांच आदेश से सप्ताह भर पहले भोपालपट्नम में पदस्थ खाद्य निरीक्षक मनोज सारथी भोपालपट्नम ब्लाक मुख्यालय में आयोजित संकल्प भारत कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद बामनपुर के सेल्समैन तुलसीराम गोटे को फोन पर कह रहे है कि वहां कोई पत्रकार पहुंचा तो नहीं अगर कोई भी कुछ पूछता है तो कह देना कि पैसे मिल गए हैं। वीडियों में सारथी सेल्समैन पर पैसे मिलने की गलत जानकारी देने का दबाव बनाते साफ सुनाई पड़ रहे हैं।

सेल्समैन को गलत जानकारी देने फोन पर दबाव बनाने के साथ कुछ और सवाल जब पत्रकारों ने पूछे तो खाद्यनिरीक्षक के माथे से पसीने छूटने लगे। कैमरे पर फूड इंस्पेक्टर सारथी का कहना था कि संचालक एजेंसी के खाते में पैसे डालना होता है जो सस्पेंड हैं, उनके खाते में पैसे डालने से समस्या होती, इसके अलावा समूह में रकम निकासी की लिमिटेशन होती है।

सेल्समैन के फोन पे और एनईएफटी के जरिए पैसे लेने के आरोप पर खाद्य निरीक्षक ने कहा कि एक शासकीय सेवक होने के नाते सरकारी पैसे मुझे अपने खाते में लेने का अधिकार नहीं, लेकिन व्यवहार में कुछ हद तक संभव, लेकिन राशि उसके व्यक्तिगत खाते से आई है वो भी डीडी बनाने के लिए। कुछ के खाते में दिक्कत थी, इसलिए राशि ली गई थी एक खाते में एक से अधिक खातों की रकम दुकानदारों की सहमति से जमा करवाए गए थे। रही बात सेल्समैन पर दबाव बनाने की तो उसे पता है कि पैसे मिलने वाले हैं इसलिए मैने उससे फोन पर कहा कि कोई भी पूछे तो पैसे मिल गए कह देना।

बोनस राशि मिलने से जनक राम के चेहरे पे आई मुस्कान, परिवार में छाई खुशहाली

■ **बकाया बोनस के रूप में एक लाख 38 हजार से अधिक की राशि हुई प्राप्त**

कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रदेश के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। धान के बकाया बोनस राशि मिलने के बाद किसान परिवार बेहद खुश है इसके साथ ही उन्हें आर्थिक मजबूती भी मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुशासन दिवस पर किसानों को धान खरीदी का बकाया बोनस राशि प्रदान किया, जिससे प्रदेश के किसान सहित उनके परिजनों में भी खुशी की लहर है।

सरकार द्वारा बकाया बोनस राशि वितरण की महत्वपूर्ण पहल किसानों की खेती संबंधी एवं परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुपयोगी साबित हो रहा है। कोरबा विकासखंड के ग्राम बरपाली निवासी किसान श्री जनक राम राठिया ने बोनस राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें बोनस राशि के रूप में एक लाख 38 हजार 840 रुपए प्राप्त हुए है। राठिया का कहना है कि किसानों की चिंता करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की इस सार्थक पहल के जरिए किसानों को बड़ी सौगात मिली है। जिससे प्रदेश के लाखों किसान परिवार खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी 36 एकड़ की पैतृक जमीन पर कड़ी मेहनत और उन्नत तकनीक अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे उनका परिवार आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी फसल की पैदावार अच्छी हुई है। लगभग 400 क्विंटल धान का विक्रय करेंगे। जनक राम ने कहा कि प्राप्त बोनस राशि का उपयोग वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने परिजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

विजय शर्मा को गृह विभाग समेत कई बड़े विभाग मिलने पर समर्थकों में जश्न

कबीरधाम। एक दिन पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। इसमें कबीरधाम जिले की कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय शर्मा को गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह हैं कि विजय शर्मा एक समय जेल में भी रहे हैं। दरअसल, अक्टूबर 2021 में कवर्धा शहर के लोहारा नाका चौक में झंडा विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद कवर्धा में धारा 144 लागू की गई थी, जो एक माह तक लगी थी। इसी विवाद में विजय शर्मा को जेल भी जाना पड़ा था। अब समय बदला और विजय शर्मा गृह-जेल मंत्री बनाए गए हैं। विजय शर्मा इससे पहले कबीरधाम जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। पंचायत विभाग की अच्छी खासी जानकारी है। यहीं कारण है कि उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। वे राजनीति से पहले रायपुर के निजी कॉलेज में अध्यापक भी रहे हैं। प्रदेश सरकार में बड़े पद मिलने के बाद कवर्धा में जश्न का माहौल है। वर्तमान में वे कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हैं। शनिवार को वे ग्राम शीतलपानी, ग्राम झलमला, ग्राम समनापुर, ग्राम सिवनीखुर्द के लोगों से संवाद किया। उनकी समस्याओं के निवारण के लिए उचित निर्देश दिए।

प्रदेश में नए उद्योग लगे और बेरोजगारों को नौकरी मिले इस दिशा में कार्य किया जाएगा

कोरबा। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर एक पखवाड़े से चल रहा इंतजार खत्म हुआ। शुक्रवार की शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों का विभाग सुनिश्चित कर दिया। मंत्रियों के विभाग बंटवारे में कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन को भी वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री बनने के बाद मंत्री लखन लाल देवांगन मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते कहा कि अभी मंत्री पद मिला है। रायपुर जाकर अधिकारियों से चर्चा और समीक्षा कर प्रदेश में कितने उद्योग चल रहे हैं, उसमें कितने श्रमिक हैं इसकी जानकारी लेंगे। इसके बाद श्रमिकों के हित में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगे और बेरोजगारों को नौकरी मिले इस दिशा में कार्य किया जाएगा। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि उद्योगों से मिलने वाले सीएसआर मद की भी जानकारी लेंगे कि कितना पैसा आता है और कितना खर्च होता है। यदि सीएसआर मद की राशि में भ्रष्टाचार हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की जो भी समस्याएं है उनके निदान की दिशा में काम किया जाएगा। श्रमिकों को शासकीय दर के हिसाब से वेतन मिले, उसमे कोई कटौती न की जाए इस और फोकस रहेगा और यदि कोई मजदूरों का शोषण करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।

दयालदास बघेल अब संभालेंगे खाद्य विभाग का जिम्मा

बेमेतरा। बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक दयालदास बघेल तीसरी बार मंत्री बने हैं। शुक्रवार को जारी विभागों के बंटवारें में उन्हें खाद्य विभाग मिला है। वे रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान 2009 में वाणिज्य-उद्योग मंत्री और 2015 में राजस्व मंत्री भी रहे है। इसके अलावा 2004 में सदस्य, प्राक्कलन व पुस्तकालय समिति विधानसभा, 2008 में उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, 2009 में विधानसभा की अलग-अलग समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं पूर्व में ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे जिला पंचायत सदस्य और भाजपा में भी कई पदों पर रहे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गुरुदयाल सिंह बंजारे से हार गए थे। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी व मंत्री गुरु रुद्र कुमार को 15 हजार से अधिक वोट से हराया है। बता दे कि मंत्रिमंडल में शामिल दयालदास एससी वर्ग के एकमात्र मंत्री है।

प्रदेश स्तरीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज का अधिवेशन रायपुर में संपन्न

रायपुर। आशीर्वाद भवन बैरन बाजार रायपुर में प्रदेश स्तरीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। अधिवेशन एक प्रकार से समुद्र मंथन जैसा रहा पदाधिकारियों ने सामाजिक एकता और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता एवं युवा शक्ति का इस ओर झुकाव के प्रति अपने विचार रखे एवं मर्यादित रूप से कार्यक्रमों को सम्माननीय ढंग से करने हेतु एकजुटता का संकल्प लिया। सभी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन एकरूपता के साथ आपसी सामंजस्य एवं तालमेल से करें तो पूरे प्रदेशवासी इसका लाभ ले सकेंगे। युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं उपनयन संस्कार जैसे परशुराम जयंती जैसे कार्यक्रम सामूहिक रूप से एवं भव्य रूप से विभिन्न शहरों एवं विभिन्न तरीकों में आयोजित करने से सभी लोग लाभान्वित होंगे सामाजिक पारिवारिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिखावा न करते हुए सादगी से करने पर सभी लोगों ने जोर दिया।

किसान और राइस मिलर्स हमारी अर्थव्यवस्था के दो पहिए: साय

कार्गो हब के निर्माण से प्रदेश में फलेगा-फूलेगा व्यापार-व्यवसाय, राईस मिलर्स के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय का समारोह में मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने ड्रायफ्रूट की माला, साफा और गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए मिलर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देते हुए नववर्ष की अग्रिम बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि धान की फसल हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान और राइस मिलर्स हमारी अर्थव्यवस्था को दो पहिए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती और गतिशीलता के लिए दोनों पहियों की मजबूती और गतिशीलता बहुत जरूरी है। यह जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। हम मिल-जुलकर प्रदेश के चावल उद्योग को नयी ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन लगातार बढ़ा है। इससे चावल उद्योग के क्षेत्र में नयी संभावनाओं का जन्म हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा चावल के महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो चुकी है। अभी छत्तीसगढ़ में परिवहन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है। अन्य राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, रेल नेटवर्क और मजबूत हो, साथ ही एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 23 वीं बैठक में छत्तीसगढ़ में कार्गो हब बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके निर्माण से प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय फलेगा-फूलेगा। कल ही राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है। परिवहन के विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हम नये आयाम स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। प्रति एकड़ धान खरीदी की यह मात्रा बीते खरीफ की तुलना में लगभग 6 क्विंटल ज्यादा है। धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 130 लाख मेट्रिक टन है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खरीदी होने की उम्मीद है। उन्होंने मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मिलर्स और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि कस्टम मिलिंग का काम बहुत तेजी से किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के कोटे का चावल सेंट्रल पूल में तेजी से जमा कराया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के सभी मिलर्स से पूरी क्षमता से और तेजी से मिलिंग करने की अपील की।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि और भगवान श्री राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ से भांचा राम के लिए सुगंधित चांवल भेजा जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राईस मील बड़ा व्यवसाय है। कृषि की प्रगति में भी राईस मिलर्स का बड़ा सहयोग है। सांसद श्री सुनील सोनी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में सांसद श्री सुनील सोनी, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री संपत अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री योगेश अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे।

अयोध्या भेजा गया 300 मीट्रिक टन चावल, सीएम साय ने ध्वज दिखाकर किया रवाना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्री राम मंदिर परिसर से 300 मीट्रिक टन चावल से भरे 11 ट्रकों को झंडी दिखाकर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना किया। इस अवसर पर रायपुर सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री दयाल दास बघेल भी उपस्थित रहे। इससे पहले श्रीराम मंदिर में सीएम साय को मोतीचूर के लड्डुओं से तौला गया। जिसके बाद भगवा ध्वज दिखाकर सीएम ने चावल से भरे ट्रकों को रवाना किया। श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए छत्तीसगढ़ से चावल के ट्रक को रवाना किया गया है। जिसे अयोध्या में होने वाले महाभंडारे में परोसा जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। साथ ही मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए तैयारी जोर-शोर से चल रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। जिसमें देश भर से आए हुए लाखों श्रद्धालु भोजन पा सकेंगे।

मुख्यमंत्री साय से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का देर रात तक लगा रहा तांता

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने वाले लोगों का देर रात तक तांता लग रहा । मुख्यमंत्री आज रायगढ़ और जशपुर जिले के गांवों के दौरे के बाद अपने गृह ग्राम बगिया में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जहां उनके निवास स्थल पर बड़ी संख्या में समाज प्रमुखों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आसपास के ग्रामीण ने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता के साथ लोगों से मुलाकात की।

जशपुर रायगढ़ अंचल का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले श्री विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र के लोगों में अपार उत्साह और खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री से मिलने लोग आसपास के क्षेत्र से लगातार आते रहे। मुख्यमंत्री को पुष्प हार, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों ने उनका अभिनंदन किया।

इस दौरान नागवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया। इसके साथ ही भुईया समाज, तुरी समाज, महकुल समाज, रौननियर समाज, डोम समाज, रौतिया समाज, मछुवा समाज, साहू समाज, सर्व आदिवासी समाज, ठेठवार समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। पत्थलगांव से आए प्रतिनिधिमंडल, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, कांसाबेल, शिक्षक संघ,वन कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ, सोढ़ी समाज, डीएवी स्कूल के शिक्षक स्टाफ, प्रेस क्लब के सदस्यों, पटवारी सचिव संघ के सदस्यों ने भी मुलाकात कर मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

हसदेव अरण्य मामले में सियासत गर्म, कांग्रेस बनाएगी कमेटी

■ इधर भाजपा सरकार करेगी एमओयू की समीक्षा

रायपुर। हसदेव में जंगल कटाई मामले में कांग्रेस कमेटी गठित कर रही है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है और आज हम लोग कमेटी का गठन कर रहे हैं। हमारी कमेटी जाएगी। हम लोग प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासियों से चर्चा करेंगे। वहां बात करेंगे। रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे इसके लिए कांग्रेस नए तरीके से रणनीति बनाएगी।

बैज ने कहा कि हसदेव बचाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहा है वो अच्छा है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में इन दोनों ने मिलकर

चंद उद्योगपति के हाथों में सौंप दिया है। हमारे जल, जंगल, जमीन को बेचा जा रहा है। खनिज संसाधन को बेचा जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी।

बता दें कि इससे पहले वन मंत्री केदार कश्यप ने भी हसदेव मामले में बयान देते हुए कहा है कि जो भी एमओयू हुआ है उस फाइल को देखूंगा। जो भी टर्म्स कंडिशंस हैं उसे देखकर आगे विचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दिखावे के लिए विरोध किया था।

जो भी हुआ है वह सब की जानकारी में है। हमारे वहां के वनवासी भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ कोई अहित न हो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे मामले को देखूंगा फिर मैं कुछ कह पाऊंगा।

वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदार मिलने पर केदार कश्यप ने कहा कि इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं।

रायपुर जंगल सफारी में 17 हिरणों की मौत का खुलासा, घातक वायरस से मिनटों में मौत

रायपुर। जंगल सफारी में 17 हिरणों (चौसिंगा) की मौत की वजह का पता चल गया है।इन हिरणों की मौत खतरनाक वायरस फूड एंड माउथ डिजीज से हुई है। जिसका खुलासा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, उत्तर प्रदेश से मिली रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट की पुष्टि मुख्य वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ राकेश वर्मा ने की है।

डॉ राकेश वर्मा ने बताया कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे चंद मिनट में ही जानवरों की मौत हो जाती है। यह वायरस जानवरों के हार्ट पर असर करता है और एक तरीके से हार्ट अटैक की वजह से जानवर की मौत हो जाती है। यह वायरस पालतू पशुओं में पाया जाता है और उन पशुओं के संपर्क में आने वाले व्यक्ति वस्तु या खाने पीने की चीज सहित अन्य कई माध्यम से दूसरे जानवरों में भी पहुंच जाता है यानी कि इस वायरस का वाहक इंसान भी हो सकता है। जंगल सफारी में 25 से 29 नवंबर तक 17 हिरणों की मौत हुई थी। हिरणों की 10 से 15 मिनट के अंदर मौत

हो गई। उनके इलाज का भी समय नहीं मिल सका। किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पता चल पा रहा था।उनकी मौत के बाद जानवरों का बिसरा इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, उत्तर प्रदेश भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इससे पता चला है कि हिरणों की मौत फूड एंड माउथ डिजीज से हुई है।डॉक्टर ने बताया कि यह रोग सामान्यत: पालतू पशु में पाया जाता है। यह संक्रामक रोग बारिश की वजह से काफी तेजी से फैलता है। भारत में सबसे ज्यादा मवेशियों की मौत इसी रोग की वजह से होती है। इस वायरस का असर सीधे जानवर के हार्ट पर होता है और कुछ ही देर में पशुओं की मौत हो जाती है या यूं कहे कि हार्टअटैक जैसा ही लक्षण देखने को मिलता है।

डॉ राकेश वर्मा ने बताया कि इस संक्रमण के जानवरों में फैलाने के बहुत सारे कारण होते हैं। हवा, आसपास के इलाकों में फैले वायरस, अन्य जानवरों के संपर्क में आना, खाने-पीने की चीज सहित अन्य वस्तुओं के माध्यम से यह वायरस दूसरे जानवर में चला जाता है। इतना ही नहीं यदि किसी के घर में पालतू जानवर है और उसमें यह वायरस है तो वह उस घर में रहने वाले व्यक्ति के जरिए दूसरे जानवरों में भी जा सकता है।

डॉ राकेश वर्मा का कहना है कि जंगल सफारी के जानवर तक के वायरस कैसे पहुंचा इसकी जानकारी लगाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के गांव में भी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि हाल फिलहाल वहां क्या इस तरह का वायरस जानवरों में पाया गया है।

वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा 14 को आचार्य चाणक्य स्मृति दिवस का आयोजन

रायपुर। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छ.ग। एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा की अध्यक्षता में शुक्रवार 29 दिसम्बर को प्रांतीय कार्यालय, प्रोसेसर कालोनी, रायपुर में आयोजित की गयी जिसका शुभारंभ श्री गणेश पूजन कर किया गया।

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि आगामी 14 जनवरी को आचार्य चाणक्य स्मृति दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें आचार्य चाणक्य जी के जीवन पर व्याख्यान एवं धार्मिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाना है, इस आयोजन में विप्र विधायकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुणनिधि मिश्रा ने कहा की सभी विप्र विधायकों को आमंत्रित करने हेतु प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगे। महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा ने बताया की कार्यक्रम में उपस्थित समस्त दर्शकों से धार्मिक प्रश्न पूछे जाएंगे और सही उत्तर देने पर सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रांतीय महासचिव अजय अवस्थी ने बताया

की तीन वक्ताओं के नाम तय कर उन्हें आचार्य चाणक्य जी पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा ने सभी सदस्यों को संगठन के कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की। बैठक के अंत में संगठन द्वारा दर्शनीय स्थल भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत 24 दिसम्बर को आयोजित तुरतुरिया धाम, बार नवापारा के भ्रमण में शामिल 42 सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में विशेष रुप से प्रांतीय महासचिव सुनील ओझा, महिला महासचिव सुमन मिश्रा, युवा सचिव अभिषेक त्रिपाठी, महिला सचिव अर्चना तिवारी, प्रांतीय सचिव सतीश शर्मा, कोषाध्यक्ष राघवेंद्र पाठक उपस्थित रहे।

साय केबिनेट में सीनियर नेताओं को किया गया दरकिनार: दीपक बैज

■ विभाग बंटवारे पर पीसीसी चीफ का बयान, बोले- छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए अनुभव का लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने और साय केबिनेट के विस्तार के बाद सभी को विभागों के आवंटन का इंतज़ार था। शुक्रवार को आखिरकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मंत्रिमंडल में विभागों के बटवारे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामनें आया हैं। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सीनियर नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि, हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से उनके पूरे शीर्ष नेता कमजोर हो रहे है। मंत्रिमंडल में जो विभागों का आवंटन हुआ उसमें पूरी तरह से सीनियर नेताओं को दरकिनार किया गया है। जिन सीनियर मंत्रियों को विभाग उनके अनुभव के आधार पर मिलना चाहिए था, उन्हें वह नहीं मिला। इसका सीधा मतलब है कि, यह सरकार दिल्ली से चल रही है, इसे दिल्ली से रिमोट कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि सीनियर नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को उनके अनुभव का जो लाभ मिलना चाहिए, वह इन्हें नहीं मिल पाएगा।

अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर छत्तीसगढ़ से जा रहे चावल को लेकर दीपक बैज ने कहा कि, अगर

छत्तीसगढ़ से चावल या धान जा रहा है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह सरकार का निर्णय है। उन्होंने कहा कि भगवान पर हमारी आस्था है, इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास समय होगा तो हम जरूर जाएंगे, नहीं होगा तो हम यहीं से दर्शन कर लेंगे।

भगवान राम वन गमन पथ का सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है। राम गमन पथ और कौशल्या माता मंदिर को लेकर जितना काम 5 साल में हमारी सरकार ने किया, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 सालों में भी नहीं हुआ। बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय भगवान राम याद आते हैं। चुनाव के बाद यह भूल जाते हैं, मतलब सामने राम-राम और बगल में छुरी। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के रूप में भगवान राम का प्रयोग कर रही है।

बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे उसमें बुरी तरीके से फसने वाली है

भाजपा सरकार बनते ही अनियमित कर्मचारी सहित कई वर्गो के लोग के अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस पहुंचने पर दीपक बैज ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जनता को जितने झूठे सपने दिखाए हैं वह सपने पूरे होने वाले नहीं है। लगातार आत्महत्या बढ़ रही है, कर्मचारी चिंतित है। संविदा कर्मचारी परेशान है, इनसे सवाल यही है कि, अगर इन्होंने वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, आज एक महीना होने के बाद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कोई ठोस निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं लिया लिया है ये उसी का नतीजा है। देश के युवा, किसान, माता बहने, कर्मचारी कहीं ना कहीं चिंतित है उसी का नतीजा है कि लगातार इस तरीके से माहौल बन रहा है। आने वाले समय में यह माहौल और विकराल रूप लेने वाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने झूठे वादे किए थे उसमें बुरी तरीके से फसने वाली है।

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 50% वोट का रखा लक्ष्य

अवधेश कुमार

बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव पर केंद्रित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 50 प्रतिशत मत पाने का लक्ष्य तय किया है। 1984 आम चुनाव में कांग्रेस को 46.86 प्रतिशत मत मिले थे। तब उसने 414 सीटें जीती थीं। ऐसे में पहला प्रश्न तो यही है कि क्या बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी? इसके बाद ही यह सवाल आता है कि क्या वह वाकई विजय का रेकॉर्ड बनाएगी? यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.7 प्रतिशत मत के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी। तब ज्यादातर विश्लेषक मानने को तैयार नहीं थे कि बीजेपी 2014 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2014 में भी ऐसे कम ही लोग थे, जो मान रहे थे कि बीजेपी लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगी। तब बीजेपी ने 31.34 प्रतिशत मत और 282 सीटें जीतकर हैरान कर दिया था। 2019 में तो राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार की हर मोर्चे पर विफलता बताई जा रही थी। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पराजय के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के अंत तक की घोषणा कर दी गई थी। इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के संदर्भ में 2018-19 जैसी तस्वीर नहीं बनाई जा रही। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेकॉर्ड जीत का दावा खारिज करने वालों के पास भी ठोस आधार नहीं हैं। आज की तारीख में बीजेपी ही 2024 में सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। आम विश्लेषक 2014 लोकसभा चुनाव में तब हिंदुत्व और हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्र चेतना के अंडरकरंट को नहीं भांप सके थे। तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा सच्चर आयोग से लेकर रामसेतु, अयोध्या आदि मामले पर लिए गए स्टैंड से एक बड़े वर्ग में आक्रोश बढ़ गया था। लगातार आतंकवादी हमले होने और उनमें पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट होने के बावजूद उसके विरुद्ध सामूहिक भावना के अनुरूप साहसी निर्णय न करने से लोगों का राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी परफॉर्मर बनकर उभरे। वह हिंदुत्व एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। उन्होंने देश की स्थिति और लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपने प्रखर विचारों से विश्वास जीता। अगर 2024 को देखें तो इन सभी कारकों के संदर्भ में मौजूदा माहौल मोदी और बीजेपी के ज्यादा अनुकूल है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में प्राणप्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। राम मंदिर आंदोलन संघ परिवार के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं पुनर्जागरण का आंदोलन रहा है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को इस रूप में जन-जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। यही नहीं, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल जैसे धर्म स्थानों के पुनर्निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अंत ने मोदी के प्रति विश्वास और सम्मान को गहरा किया है। अगले कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विश्व की महाशक्ति बना देने का उनका वादा लोगों के दिलों में जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष में सनातन, हिंदू धर्म और हिंदी भाषी राज्यों आदि पर इंडिया घटकों के आपत्तिजनक बयानों और इन पर कांग्रेस सहित ज्यादातर पार्टियों की चुप्पी के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो मोदी और बीजेपी के पक्ष में जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तीसरे कार्यकाल के साथ मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा होगी। मोदी 75 वर्ष की उम्र सीमा 2026 में पूरी करेंगे। हालांकि पार्टी के संसदीय बोर्ड में ज्यादा उम्र के नेता आए हैं और संघ ने भी उसे स्वीकार किया है। संकेत यही है कि 75 की उम्र सीमा आगे कायम नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी का स्वास्थ्य, उनकी कार्यक्षमता और उनके द्वारा घोषित भविष्य के बड़े लक्ष्यों को देखते हुए संगठन परिवार उन्हें तत्काल रिटायर होने देना नहीं चाहेगा।

चापलूसी संस्कृति से चमक खोती कांग्रेस

ललित गर्ग

कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के प्रति चापलूसी की पुरानी परंपरा रही है, इस परंपरा को कांग्रेसी नेता पार्टी की संस्कृति की तरह से अपनाते रहे हैं। ऐसे अनेक नेता हुए हैं, जिन्होंने उस परंपरा को परवान चढ़ाने की मिसाल कायम करके सुर्खियां बटोरीं हैं, लेकिन इससे सबसे सशक्त एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का क्या हश्र हो रहा है, इस बात को देखने का साहस पार्टी के भीतर किसी नेता में नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक वोट बैंक वाली पार्टी होने के बावजूद वह कोई सार्थक परिणाम एवं प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही हैं। हाल ही में सम्पन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उसने करारी हार का सामना किया है। इन राज्यों में हुए चुनावों में या तो कांग्रेस की सरकार जाती रही या विपक्ष में होने का बावजूद भी वो वहां कुछ ख़ास कमाल नहीं कर सकी। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई ख़ास कमाल नहीं कर सकी। पूर्व में सम्पन्न हुई राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की भांति आगामी न्याय यात्रा कोरा चापसूसों का जमावड़ा होकर रह जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है।

भारतीय राजनीति के अमृतकाल तक पहुंचे शासन में से लगभग पचास साल कांग्रेस का राज रहा है। प्रश्न है कि ऐसे क्या कारण है कि अब कांग्रेस सत्ता से दूर होती जा रही है। कद्दावर एवं राजनीतिक खिलाड़ियों की पार्टी होकर भी वह अपना धरातल खोती जा रही है। इसका कारण परिवारवाद एवं चापलूसी राजनीतिक संस्कृति ही है। इसी कारण अनेक पार्टी-स्तंभ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में जीना चाहती है कि वंशवादी नेतृत्व ही उसका उद्धार करेगा तो उसे ऐसी गलतफहमी पालने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम भी उसे झेलने ही होंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी से जुड़े हर ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता एवं नेता को उचित अनुचित का बोध नहीं है। वे सब कुछ जानते हुए भी मक्खी निगलते हैं? आखिर क्यों? इसीलिए कि जिंदगी भर चापलूसी करते-करते जी-हूजुरी या चमचागिरी करना ही उनका बोध रह गया है।

नेता को सारे अधिकार समर्पित करके हमारे देश के पार्टी कार्यकर्ता अपनी बुद्धि एवं विवेक को स्थायी तौर पर निस्तेज एवं गूंगा बना देते हैं। इसी के चलते लोकतंत्र की ओट में नेतातंत्र पनपने लगता है। उसका आखरी अंजाम होता है, राजनीति का पतन। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता अपनी पार्टी, सरकार, संसद और यहां तक कि देश को भी दांव पर लगा देता है। चापलूसी खुद को तो आगे बढ़ा देती है, लेकिन बाकी सबको पीछे ढकेल देती है। चापलूसी का मक्खन राजनीति की राह को इतनी रपटीली बना देता है कि उस पर नेता, पार्टी और देश, सभी चारों खाने चित हो जाते हैं। चापलूसी का दरवाजा खुलते ही प्रश्नों की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। लगातार रसातल ही ओर जा रही कांग्रेस की इस स्थिति का कारण भी यही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कब समझेगा कि चापलूसी एक नकली सिक्का है और नकली सिक्कों की बदौलत उन्नति नहीं, अवनति ही झेलनी पड़ती है।

कांग्रेस को चापलूसी का घुन खोखला कर रहा है। यूं तो प्रारंभ से ही कांग्रेस चापलूसियों का गिरोह रही है। राजनीति की द्वंद्वात्मकता को समाप्त करने में चापलूसी मुख्य भूमिका निभाती है। चापलूसी ने भारतीय राजनीति को वंशवादी, सम्प्रदायवादी, जातिवादी बना दिया है। नेता का हित ही पार्टी का हित है, देश का हित है। इस संकीर्ण चरित्र ने पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र को मरणासन्न कर दिया है। अगर पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो वह देश में कैसे रह सकता है? संकट की घड़ी में वह धराशायी हो जाता है। हमारे आज के नेता कोई महात्मा गांधी की तरह नहीं हैं कि उनके सद्गुणों को उनके अनुयायी लोग अपने जीवन में उतारे। नेता वैसा आग्रह करते भी नहीं और अनुयायी वैसा करना जरूरी भी नहीं समझते। इसीलिए हमारी राजनीति ऊपर से चमकदार और अंदर से खोखली होती जा रही है। जो अपने इर्द-गिर्द चापलूस लोगों की भीड़ देखने के आदी होते हैं, उन्हें हर जगह यही अपेक्षित होता है। आज इंडिया गठबंधन में बिखराव का भी बड़ा कारण यही चापलूसी संस्कृति है।

कांग्रेस में चापलूसी का इतिहास पुराना रहा है। अपने नेता का महिमामंडन करने के लिये कार्यकर्ता क्या-क्या नहीं करते एवं कहते हैं। कभी तत्कालीन कपड़ा मामलों के मंत्री रहे शंकरसिंह वाघेला ने महात्मा गांधी के बाद भारतीय इतिहास में त्याग करने वाले लोगों में सोनिया गांधी को माना। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी की मां नहीं हैं। हम सब की मां हैं। वे सारे देश की मां हैं!' संवेदनशील भारतीय इससे चौंके ही नहीं, बुरी तरह क्रोधित भी हुए हैं। यह भारत का अपमान था, यह 'मां' जैसे सर्वोच्च रिश्ते का अपमान था। लेकिन अपमान करने में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, खुद सोनिया, राहुल एवं अन्य नेताओं ने कोई कमी नहीं रखी। राहुल गांधी जैसे नेता ने प्रधानमंत्री को पनौती करार दे दिया। वनडे विश्व कप फाइनल में भारत की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जेबकतरा भी करार दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि आप जो कुछ खरीदते हैं उसका पैसा सीधे अदाणी की जेब में जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने मर्यादा, शालीनता एवं शिष्टता का चीरहरण ही कर दिया। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में यह दम नहीं कि वह अपने नेताओं से पूछे कि आप देश के प्रधानमंत्री के लिये विषवमन करके किस तरह पार्टी का हित कर रहे हैं?

बात केवल कांग्रेस की ही नहीं, सभी दलों की है। दलों में चापलूसी गहरी पैठ गयी है। लगातार पांव पसार रही इस विसंगति के कारण अनेक दल आज अपने अस्तित्व एवं अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिन दलों ने इस विसंगति से दूरी बनायी, वे लगातार अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बना रहे हैं। राजनीति के इस चापलूसीकरण के कारण ही देश के श्रेष्ठ और स्वाभिमानी लोग राजनीति से परे रहते हैं। राजनीति में घुसने और आगे बढ़ने के लिए सिद्धान्त एवं मर्यादाहीन नेताओं के आगे इतनी नाक रगड़नी पड़ती है कि जिन लोगों में देश-सेवा एवं शुद्ध- राजनीति की ललक है, वे भी घर बैठना ज्यादा सही समझते हैं। नेतागण केवल उन्हीं लोगों को अंदर घुसने देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जो उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति करें। अनेक नामी-गिरामी उद्योगपति, पत्रकार, फिल्म अभिनेता और विद्वान भी राजनीति में गए हैं, लेकिन उन्हें इसीलिए स्वीकार किया गया है कि वे साफ-साफ या चोरी छिपे किसी नेता की चमचागिरी करते रहे हैं। उनसे अधिक प्रसिद्ध और उनसे अधिक योग्य लोग अपने घर बैठे हैं।

चापलूसी के घेराबंदी का ही परिणाम है कि कांग्रेस में सही को सही एवं गलत को गलत ठहराने का निर्णय लेने वाला कोई साहसी नेता नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी मोदी विरोध के नाम पर देश के विरोध पर उतर जाते हैं। वे इस तरह का आचरण इसीलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी संचालन एवं राजनीतिक परिपक्वता के तौर-तरीकों का कोई अनुभव नहीं। उनकी तरह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी कोई जिम्मेदारी लिए बिना पर्दे के पीछे से सब कुछ करने में ही यकीन रखती हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वह गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकती। कांग्रेस नेताओं की भी यह विवशता है कि अपने नेता के बयानों को सही एवं जायज ठहराने में सारी हदें लांघ जाते हैं। लेकिन, प्रश्न यह है कि क्या दुश्मन राष्ट्र से जुड़ी स्थितियों पर बोलते हुए वह मात्र भारत के विपक्षी दल के नेता होते हैं? क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भारत का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यह समस्या मात्र राहुल गांधी की नहीं है। पूरा विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा है कि सत्ताधारी दल के विरोध और देश के विरोध के बीच फर्क है। सत्ताधारी दल का विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन उस लकीर को नहीं पार करना चाहिए, जिससे वह देश का विरोध बन जाए। ऐसे बयानों से किस पर और कैसे प्रभाव पड़ता है। सरकार और राष्ट्र के विरोध के बीच अंतर समझना भी आवश्यक है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद्

यह उपनिषद् अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसमें वालखिल्य ऋषि एवं स्वयंभू ब्रह्माजी के बीच हुए हंस सूत्र विषयक प्रश्नोत्तर का वर्णन है। यह उपनिषद् दो काण्डों (पूर्वकाण्ड और उत्तरकाण्ड) में प्रविभक्त है। पूर्वकाण्ड में सर्वप्रथम जगत् नियन्ता के विषय में सात प्रश्न किए गये हैं, जिनका क्रमशः उत्तर दिया गया है। तत्पश्चात् सृष्टियज्ञ में कर्तृता का निरूपण, नादानुसन्धान यज्ञ, परमात्मा का हंस रूप, यज्ञसूत्र एवं ब्रह्मसूत्र में साम्य, प्रणव हंस का यज्ञत्व, ब्रह्मसन्ध्या का क्रियारूप मानसिक यज्ञ, हंस और प्रणव का अभेदानुसंधान, 96 हंस सूत्र हंसात्मविद्या से मुक्ति, बाह्य यज्ञ की अपेक्षा आन्तरिक यज्ञ की श्रेष्ठता, ज्ञान यज्ञरूप अश्वमेध तथा तारकहंस ज्योति का वर्णन है।

उत्तरकाण्ड में सर्वप्रथम ब्रह्मसम्पत्ति का तत्पश्चात् परमात्मा में जगत् का आविर्भाव मायाजन्य, हंसार्कप्रणव ध्यान की विधि, शिव द्वारा मन तथा इन्द्रियों की प्रेरकता, आत्मा में अन्य की अनुभूति माया जन्य, आत्मज्ञानी की ब्रह्मात्मता, सत्यादि श्रेष्ठविद्या का साधनत्व, आत्मज्ञानी की आवागमन से मुक्ति, ब्रह्मज्ञानी के लिए भक्ष्याभक्ष्य विवेक की अनुपयोगिता और अन्त में ज्ञानी द्वारा अपने में सभी के दर्शन करने की स्थिति का वर्णन है। इस प्रकार ब्रह्मविषयक गूढ़ सिद्धान्तों का बहुत विशद वर्णन इस उपनिषद् में किया गया है।

एक बार स्वयंभू भगवान् ब्रह्माजी के मन में यह आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई कि मैं प्रजा का सृजन करूँ। उसी सृष्टि क्रम में कामेश्वर (रुद्र) एवं वैश्रवण की उत्पत्ति हुई।

तदुपरान्त ब्रह्मपुत्र वैश्रवण वालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्माजी से प्रश्न किया- हे भगवन! यह जगत् विद्या क्या है ? जाग्रत् और तुरीयावस्था के देवता कौन हैं? यह जगत् किसके वश में है? काल का क्या प्रमाण है ? सूर्य एवं चन्द्रादि ग्रह किसकी आज्ञा से प्रतिभासित (प्रकाशित) होते हैं? किसकी महिमा गगन के सदृश विशाल है ? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई इन प्रश्नों का ज्ञाता नहीं है, अतः हे ब्रह्मन! आप कृपा करके इन प्रश्नों को बताने का अनुग्रह करें।

क्रमशः ...

सैयद जहूर कासिम

सैयद जहूर कासिम का जन्म 31 दिसंबर 1926 को हुआ था। उनका जन्म इलाहाबाद के रुक्सावारा गांव मे हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माजिदिया इस्लामिया इंटरमिडिएड कॉलेज इलाहाबाद से पुरी की थी। और फिर 1947 मे अलीगढ मुस्लिम विश्वाविदयालय मे दाखिला लिया था। उन्होंने 1949 मे एएमयू अलीगढ से बी एससी की डिग्री पास की थी। और फिर उसी विश्वाविध्यालय से जुलॉजी मे एम एस सी की पढाई पूरी की थी। जहॉ उनका प्रथम क्रमांक आया था। उन्हें युनिवर्सिटी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था।

जहुर काशिम जुलॉजी विभाग मे एएमयू मे व्याख्याता रह चुके थे। और फिर 1953 मे उच्चा अध्यायनन के लिए युनाइटेड किंगडम चले गए थे। उन्होंने नॉर्थ वेल्सा के युनिवर्सिटी कॉलेज मे दाखिला लिया था। और 1956 मे डी एस सी और पीएचडी की थी। वो भारत मे दिसंबर 1956 मे एएमयू मे फिर से शामिल हुए थे और बाद मे 1957 मे एक पाठक बन गए थे। उन्होंने तब समुद्री विज्ञान के क्षेत्र मे अपने कायौ मे सुधार के लिए अपने विभाग मे मछली और मत्सा पालन की एक नई प्रयोगशाला शुरु कि गई थी।

डॉ कासिम ने 1962 मे केंद्रीय मत्स्या शिक्षा संस्थान, बॉम्बे मे मत्स्या जीव विज्ञान पठाया था। 1964 मे उन्होने वैज्ञानिक और औघोगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान IIOE मे एक साहायक निदेशे के रुप मे शामिल हो गए थे। जहाँ उन्होंने केरल बैकवाटर्स कि प्राथमिक उत्पादकता और लक्षव्दीप के एटोल पर जैविक समुद्रा विज्ञान पर अपना शोध किया था। उनके साथ उन्होंने लगभग एक साल तक कोच्चि के केंद्रीय मत्स्या प्रौघोगिकी संस्थान का एक प्रभारी बनाए रखा था।

सैयद जहुर कासिम एक भारतीय समुद्री जीवविज्ञानी थे। कासिम ने अंटार्कटिका के लिए भारत की खोज का नेतृत्वा करने मे मदत की और 1981 से 1988 तक अन्या सात अभियानों का मार्गदर्शन किया था। वह 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्या थे। 1989 से 1991 तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति थे। 1953 मे उच्चा अध्ययन के लिए युनाइटेड किगडम मे आगे बढने से पहले अलीगढ मे जुलॉजी विभाग मे व्याख्याता थे ।

उनहेांने मत्स्या जिवविज्ञान, प्राथमिक उत्पाकदता समुद्रीः संस्कृति विशेष रुप से मुसल और पर्ल कल्चर, एस्टुरीन परिस्थितिकी और पर्यावरण प्रदूषण पर बडे पैमाने पर शोध किया था। जिस पर 200 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुए है । डॉ.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन डीएमआरएफ की स्थापना मुख्या रुप मे डॉ कासिम ने अपने सहयोगियों की मदद से की थी।

चुनावी साल में चुनौतियों का भी अंबार

अमिताभ श्रीवास्तव

अनेक छोटे-बड़े राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रमों के साथ एक और साल बीतने जा रहा है। गुजरते साल की अपनी चुनौतियां थीं, जो आयीं और गयीं। हालात को देखते हुए आने वाले साल में तय है कि मुश्किलें कम न होंगी। चुनावी साल के चलते जन आकांक्षाओं का ढेर बना रहेगा और आंदोलनों से राजनीतिक दलों की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि स्थानीय निकायों से लेकर देश की सर्वोच्च संसद तक के प्रतिनिधियों का चयन जनता के हाथ में होगा, जिसमें कुछ 'पास' और कुछ 'फेल' होंगे। किंतु देश और राज्य में गर्माहट का माहौल साल भर बना रहेगा।

हर बार की तरह गुजरते साल में महाराष्ट्र अनेक राजनीतिक घटनाक्रमों का साक्षी बना। लंबे समय तक राज्य में राजनीतिक विवादों का केंद्र रहे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आखिरकार अपने पद से मुक्त करने का ऐलान करना पड़ा। यद्यपि वह पद छोड़कर अपने फैसलों के चलते चर्चाओं में बने रहे। उनकी जगह छत्तीसगढ़ से सात बार सांसद रहे और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए और उसके बाद से हमेशा राजनीति के भूकंप का केंद्र बनने वाला राजभवन शांत समुद्र हो गया। किंतु उसके बाद मई माह में फिर एक बार राजनीतिक भूचाल आया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। मगर नाटकीय घटनाक्रम दो ही दिन चल पाया और उसके बाद पवार ने अपना त्याग-पत्र वापस लेकर अपने समर्थकों की इच्छा अनुरूप पूर्व पद पर बने रहने का फैसला किया। हालांकि इस पूरी गतिविधि में कहीं एक चिंगारी छूट गई, जिससे राकांपा में जुलाई में बड़ा विस्फोट हो गया और अजित पवार चाचा का साथ छोड़कर आक्रामक अंदाज में राज्य की शिंदे सरकार में शामिल हो गए।

यही नहीं, उन्होंने पूरी पार्टी तोड़कर अनेक प्रमुख नेताओं को अपने साथ लेने की कोशिश की। उनमें से कुछ को मंत्री बनवा कर अपना कद बढ़ा लिया. इसके साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को छोड़ लगभग सभी दलों के दो से तीन टुकड़े तक हो गए। अतीत में शिवसेना पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और बाद में शिंदे गुट के रूप में टूटी, जबकि कांग्रेस दो दशक से अधिक समय पहले राकांपा के रूप में विभाजित हुई और उसके बाद इस साल राकांपा आपस में ही चाचा-भतीजे के नाम पर बंट गई। इस परिदृश्य में राज्य में अब नौ से दस राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक बिसात रचने की तैयारी हो गई है।

नए परिदृश्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुकाबला मनसे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा का मुकाबला अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा से है। कांग्रेस इन टूट-फूट के बीच जोड़-घटाकर अपना भविष्य देख रही है, तो भाजपा भी नफा-नुकसान समझ कर हाथ आगे बढ़ाने में भलाई समझ रही है। इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसे चुनाव में दलित समाज की मुख्य पार्टी माना जा सकता है, के झुकाव पर बाकी गठबंधनों की नजर है। यदि वह स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान किसे और कहां होगा, इस बात का भी अंदाज लगाया जाना है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) कुछ स्थानों पर अपनी ताकत दिखा सकती है। वर्तमान में उसके पास एक सांसद तथा दो विधायक हैं। साथ ही अनेक स्थानीय निकायों में उसके प्रतिनिधि भी हैं। लिहाजा उसको चुनाव को प्रभावित करने वाला अपने मतदाताओं का आधार है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के अलग-अलग गुटों को मिलाकर महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बहुत साफ नहीं दिख रहा है। मतदाताओं को काफी उलझाने और समझाने के बाद ही चुनाव की तस्वीर साफ नजर आएगी।

राज्य में जहां सत्ताधारी दलों के लिए चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में बनाना एक चुनौती है, तो दूसरी ओर कई नई-पुरानी समस्याएं अपनी जगह समाधान मांग रही हैं। मौसम का बनता-बिगड़ता मिजाज खेती-किसानी से लेकर आम जन की जरूरत पेयजल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है।

छह माह से चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। औद्योगिकीकरण की धीमी गति, आधारभूत विकास में बाधाएं तथा विलंब, महंगाई और बेरोजगारी के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए समाज का एक वर्ग कुंठा में जीवन व्यतीत कर रहा है। नेताओं की राजनीतिक असफलता और पहचान का संकट अपनी जगह कुछ जटिल समस्याओं को हवा देता रहता है। इससे निपटना सत्ताधारियों के लिए सहज नहीं है। जैसे-जैसे चुनाव का वातावरण तैयार होगा, वैसे-वैसे सरकार और प्रशासन को नई चुनौतियां देने के प्रयास आरंभ होंगे। उसे साल में दो से तीन बार तक इनके बीच से गुजरना होगा।

चुनावी साल सत्ताधारियों के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही विपक्ष के लिए भी है. बीते समय में राज्य के सभी प्रमुख दलों ने सत्ता सुख को भोगा है। इसलिए अपनी जवाबदेही से कोई मुकर नहीं सकता। कोरोना महामारी के दो साल भी सभी के लिए चुनावी परीक्षा में कठिन प्रश्नों के रूप में शामिल होंगे। हालांकि राजनीतिक दल अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कमियों और खूबियों से माहिर ही रहते हैं, लेकिन वर्तमान में मतदाता की जागृति और नेताओं की जवाबदेही पर उठते सवाल मतदान के समय निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए गलतफहमी में जीकर सत्ता की बागडोर हासिल नहीं की जा सकती है। यदि नेतृत्व करना है तो परिणाम देने ही होंगे. विकास की संकल्पना को साकार कर दिखाना होगा। जाति और धर्म के भेद से छोटे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊंचाइयों को छूने के लिए वृहद दृष्टिकोण और सर्वांगीण विकास की अवधारणा ही काम आ सकती है। फिलहाल चुनौतियों से मुकाबला सभी का है और केवल दोषारोपण से बात नहीं बन पाएगी। नए साल में प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कुछ आगे की बात बन पाएगी।

आज का इतिहास

1972 निकारागुआ भूकंप के पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए एक प्लैनक्रैश एन मार्ग में प्यूर्टो रिकन बेसबॉल खिलाड़ी रॉबर्टो क्लेमेंटे की मृत्यु हो गई।
1983 मेजर-जनरल मुहम्मदू बुहारी को नाइजीरिया के बाद एक सफल सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जिसने नागरिक नागरिक शेहू शगारी को उखाड़ फेंका।
1983 यूनाइटेड किंगडम ने ब्रुनेई को स्वतंत्रता प्रदान की।
1986 तीन असंतुष्ट कर्मचारियों ने डुपोंट प्लाजा होटल सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में आग लगा दी, जिसमें 98 लोग मारे गए और 140 अन्य घायल हो गए, जिससे यह संयुक्त राज्य के इतिहास में दूसरी सबसे घातक होटल आग बन गई।
1986 सान जुआन के प्यूर्टो रिको के ड्यूपॉट प्लाजा होटल में आग लगने से 97 लोग मारे गए और 140 घायल हुए।
1993 ब्रैंडन टेना, एक अमेरिकी ट्रांस मैन, नेहबॉल्ड, नेब्रास्का में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी; उनकी मृत्यु के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में घृणा अपराधियों की पैरवी बढ़ गई।
1998 यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म ने यूरोज़ोन में रूपक मुद्राओं की वैल्यूज़ को फ्रीज़ कर दिया और यूरोकॉरेबिलिटी का मान स्थापित किया।
1999 रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येलत्सीन ने त्यागपत्र दे दिया और विलादमीर पुतीन उनके उतराधिकारी बने।
1999 बोरिस येल्तसिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौपा गया।
1999 रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने इस्तीफा दिया और व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया।
1999 पनामा ने 1977 के टोरिजोस-कार्टर संधियों के अनुसार, यूनाइटेडस्टेट्स से पनामा नहर क्षेत्र का नियंत्रण ले लिया।
2004 ब्यूनर्स आयर्स (अर्जेन्टीना) के एक नाइट क्लब में आग लगने से 175 लोगों की मौत।
2010 ट्यूनीशिया में, बेरोजगारी और रहने की स्थिति पर जारी विरोध के दौरान एक रक्षक की मृत्यु हो जाती है।
2010 प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने की इटली की योजना लागू हुई; देश प्रति वर्ष 20 बिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहा था - लगभग 300 प्रति व्यक्ति।
2011 हॉलीवुड में 35 आग की एक स्ट्रिंग 5 घंटे की समय सीमा के भीतर जलती है, जिससे कम से कम .350,000 का नुकसान होता है।
2011 उत्तर कोरिया में किम जोंग-उन को उत्तर कोरिया के सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर की टाइल दी जाती है।

सदन के सभापति को तटस्थ रहने की जरूरत

कपिल सिब्बल

मई 2014 में, नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने से पहले पुराने संसद भवन की सीढ़ियों पर घुटने टेकते हुए अपना माथा टेका था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में लोकतंत्र की शुरुआत करते हुए अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। लेकिन संसद के भव्य सदनों में लोकतंत्र को पोषित करने के बजाय, इसे दबाया जा रहा है। मोदी के राज में उसका दम घुट रहा है।

इतिहास को नष्ट करने का प्रयास, सांस्कृतिक आधिपत्य प्रदर्शित करने वाले स्मारकों का निर्माण, विभाजनकारी एजेंडे को प्रोत्साहित करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, अन्यायपूर्ण समझे जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों के विरोध को दबाने के लिए संस्थागत शक्ति का दुरुपयोग करना और मुकदमा दर्ज करने की धमकी से लोगों को चुप कराना एक सुनियोजित उद्यम का हिस्सा है, जिसे तथाकथित हिंदू आस्था की छत्रछाया में वैधता दिलाने की कोशिश हो रही है। सरकार और भाजपा की सभी पहलों को धार्मिक रंग देना एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जो हमारे उन संवैधानिक मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत तरीके से कार्य करना चाहता है, जो कि शासन का एकमात्र धर्म है या होना चाहिए।

संसद में हाल की घटनाओं और उनके परिणामों से पता चलता है कि मोदी के भारत ने इस धर्म का उल्लंघन किया है और सरकार के कार्य हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं। हमारी संप्रभुता के प्रतीक संसद में उपद्रवियों ने घुसपैठ की. सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारी तबाही हो सकती थी, जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन को खतरा हो सकता था। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों सदनों में एक बयान देंगे, न केवल अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए बल्कि सांसदों को यह आश्वासन देने के लिए कि ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी ताकि ऐसा सुरक्षा उल्लंघन दोबारा न हो। इस तरह के बयान की विपक्ष की मांग जायज होते हुए भी खारिज कर दी गई।

इस तरह की मांग को बहुत कम सम्मान देने, बल्कि तिरस्कार दिखाने के कारण विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसका असर संसद के दोनों सदनों के कामकाज पर पड़ा। नतीजा था 146 निलंबन, 100 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से। एक और घटना हुई जिसमें

लोकसभा के एक सदस्य ने राज्यसभा के सभापति के कार्यवाही के संचालन के तरीके पर गुस्सा व्यक्त किया। सभापति ने इस मुद्दे को उठाया और इसे जातिगत पूर्वाग्रह करार दिया और कहा कि इस तरह की 'मिमिक्री' उस जाति का भी अपमान है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने उस कृत्य को एक अनपेक्षित मोड़ दे दिया, जिसे सभापति की जाति का अपमान नहीं माना जा सकता था।

लोकसभा अध्यक्ष, हालांकि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होते हैं, वह सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्ता में बहुमत दल का नहीं। यही बात राज्यसभा के सभापति पर भी लागू होती है। अपनी-अपनी क्षमताओं में, वे अपने-अपने सदनों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता। यदि इस संवैधानिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इन पदों पर बैठे लोग सत्तापक्ष के प्रति पक्षपाती नजर आने लगते हैं। यह गहरी चिंता का विषय है. एक तो यह सदन की कार्यवाही को दूषित करता है और कार्यवाही को राजनीतिक रंग देता है। दूसरा, यह उन आरोपों का रास्ता खोलता है जो आदर्श लोकतंत्र में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं लगाए जाने चाहिए। सदन की कार्यवाही कभी भी इस तरह से नहीं चलनी चाहिए जिससे लगे कि विपक्ष पर दबाव डाला जा रहा है और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। आसन की ओर से बार-बार दिए जाने वाले निर्देश जो विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर जनता के बीच प्रसारित होने से रोकें, जब विपक्षी सदस्य विरोध कर रहे होते हैं तो उनके माइक्रोफोन को बार-बार बंद कर देना, सदस्यों को उनके कथित आचरण के लिए फटकार लगाना- ये ऐसे मामले हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि जिस गरिमा के साथ सदन की कार्यवाही चलाई जानी चाहिए, उस गरिमा के साथ वह नहीं चलाई जाती है।

इतिहास बताता है कि अतीत में उस राजनीतिक दल के सांसद जो आज सत्ता पक्ष में हैं, ने लोकसभा के पूरे सत्र को ही ठप करना सुनिश्चित किया था. भाजपा के पास विपक्ष की आवाज को दबाने का कोई नैतिक आधार नहीं है, खासकर तब जब उनकी मांग जायज थी। इसके अलावा, सत्ता पक्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि विपक्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा न करने पाए। यदि विपक्ष को राष्ट्रीय हित के मामलों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिकार से वंचित किया जाता है, यदि विपक्ष को उस तरीके से अपमानित किया जाता है जैसा हमने हाल के दिनों में देखा है, यदि विपक्ष के सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है, यदि विशेषाधिकार समिति का संचालन ऐसे तरीके से किया जाता है जो निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यही वह संसदीय लोकतंत्र है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था. इसका स्पष्ट उत्तर जोरदार 'नहीं' है। तो अब हम यहां से कहां जाएंगे? यदि भाजपा को सत्ता में एक और कार्यकाल दिया जाता है, तो असहिष्णुता कई गुना बढ़ जाएगी। लोकतंत्र ठप हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वह केवल एक खोल मात्र रह जाएगा। इस नैरेटिव को बदलना इस देश के लोगों पर निर्भर है।

अटल बिहारी वाजयेपी का एक और सपना पूरा करेगी भाजपा

विनोद पाठक

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक और सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया है। वर्ष 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। उन्होंने 31 रिवर इंटरलिंक्स चिन्हित किए थे, लेकिन अटल सरकार लोकसभा चुनाव हार गई। केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आने से यह प्रोजेक्ट दस साल तक ठंडे बस्ते में रहा और यह सपना अधूरा रह गया। वर्ष 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद एक बार फिर नदी जोड़ो परियोजना की फाइलों को निकाला गया। नदियों को जोड़ने की उम्मीद जागी। केन और बेतवा नदियों को लेकर जोड़ने को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार में सहमति बन गई है और काम शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान भी पार्वती-कालीसिंधु-चंबल (पीकेसी) नदियों को जोड़ने के लिए सहमति बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान में नई हरित क्रांति की शुरुआत हो सकती है। नए पीकेसी लिंक से पानी के लिए तरस रहे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में न केवल अगले 30 साल तक पीने का पानी सुचारू रूप से मिलता रहेगा, बल्कि 7 लाख हेक्टेयर नई भूमि सिंचित भी होगी। मध्य प्रदेश में मालवा और चंबल क्षेत्र में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस नए लिंक को राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के साथ जोड़ा जाएगा। इसको नया नाम ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट दिया गया है। दरअसल, ईआरसीपी की कवायद वर्ष 2016 में राजस्थान की भाजपा नेतृत्व वाली वसुंधरा राजे सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने एक डीपीआर भी तैयार करा ली थी, लेकिन डीपीआर में खामी के चलते प्रोजेक्ट में विलंब हुआ। डीपीआर में सुधार होता, उससे पहले वर्ष 2018 में राजस्थान में सरकार बदल गई। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तो उसने खामी वाली डीपीआर को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उस समय मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान के साथ सहमति नहीं बनाई। फिर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में अशोक गहलोत सरकार आपस में पानी को लेकर राजनीति में फंसते चले गए। कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में इस मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया। बजट में कुछ धन भी ईआरसीपी के नाम पर रखा, लेकिन राज्य अपने संसाधनों से इसे पूरा नहीं कर सकता था, यह बात अशोक गहलोत भलीभांति जानते थे। पहले से माना जा रहा था कि यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट को एक बार फिर गति मिल सकती है। ऐसा हुआ भी। जैसे ही दोनों राज्यों में भाजपा नेतृत्व की सरकार बनी, केंद्र में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले से इस लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा करते आ रहे थे, सक्रिय हो गए। अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शेखावत ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनाकर बजट स्वीकृत किया जा सकता है। भाजपा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों के वोटर्स को साधना चाहती है। यह प्रोजेक्ट नौ लोकसभा सीटों जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटा, दौसा, भरतपुर, धौलपुर-करौली, टोंक-सवाईमाधोपुर, बारां-झालावाड़ पर भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 90 प्रतिशत राशी यानी 45,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। शेष 10 प्रतिशत की राशि राजस्थान और मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में होने वाले खर्च में से देंगे। राजस्थान को 3725 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। 5 साल से अटका यह प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो पूर्वी राजस्थान में एक नई हरित क्रांति देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंधु-चंबल के बाद देश के शेष 29 रिवर इंटरलिंक्स पर भी सहमति बनाकर काम शुरू जाए।

'झांकी' को लेकर न खड़ा हो सियासी संकट

रमेश ठाकुर

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच 'झांकी' को लेकर बवाल मचा हुआ है. विवाद दरअसल ये है कि आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परेड में दिल्ली की 'झांकी' को अनुमति नहीं मिली है। परेड समिति ने दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट कर दिया। कारण बताया कि परेड के माध्यम से केजरीवाल राजनीति करना चाहते हैं। अपने कामों का प्रचार चाहते हैं। बहरहाल, किस प्रदेश की झांकी को शामिल करना, किसे नहीं, ये निर्णय तो हो चुका है। 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली और पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया जाएगा। ये सूचना जब से केजरीवाल को मिली है, वह तमतमाए हुए हैं। बकौल केजरीवाल, झांकी की तैयारी वह बीते सितंबर माह से कर रहे थे। इस बार दिल्ली सरकार की योजना थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को झांकी के जरिये प्रस्तुत कर न सिर्फ हिंदुस्तान को, बल्कि समूचे संसार को दिखाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति समारोह के मेहमान हैं, वो भी देखेंगे कि दिल्ली की हुकूमत स्वास्थ्य-शिक्षा पर अच्छा काम करती है। लेकिन केंद्र ने केजरीवाल की तैयारियों पर पानी फेर दिया। बहरहाल, झांकियों को शामिल करने की एक प्रक्रिया होती है। राज्यों की तरफ से कुछ माह पहले प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को थोड़ा विलंब हुआ। यह लगातार तीसरा गणतंत्र दिवस होगा, जब दिल्ली की झांकी देश के मुख्य समारोह का हिस्सा नहीं होगी। इससे पहले वर्ष-2021 में दिल्ली की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। तब, चांदनी चौक में किए गए री-डेवलपमेंट की थीम पर आधारित झांकी निकाली गई थी। लेकिन इस दफे केजरीवाल अपने राजनीतिक मॉडल की प्रस्तुति चाहते थे। विवाद यहीं से आरंभ हुआ। समिति ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा भी था कि दिल्ली अपनी संस्कृति की छवि झांकी के माध्यम से पेश कर सकती है, पर केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे तब हार कर समिति ने निर्णय लिया। वहीं, दिल्ली सरकार मानती है कि अमृतकाल का दौर चल रहा है इसलिए उन्होंने 26 जनवरी पर 'विकसित भारत' की थीम पर आधारित झांकी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें दिल्ली के विकास की नई तस्वीर पेश होती। झांकी में दिल्ली के नए सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों के मॉडल को दर्शाना था, जिसने राजधानी को एक नई पहचान दिलाई है पर केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी को यह थीम नहीं जंची और रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली के अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब की भी झांकी को परेड में शामिल नहीं करने का निर्णय किया है जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस निर्णय को पंजाबियों के अपमान से जोड़ दिया है। पंजाब की झांकी में कृषि कानून आंदोलन के वक्त सैकड़ों जान गंवाने वाले किसानों को दिखाना था। इसके अलावा पंजाबी खेती, खानपान और आर्मी गतिविधियों को प्रदर्शित करना था, लेकिन उन्हें भी अनुमति नहीं मिली।

सुविधाजीवी नेताओं का सियासी संकट

आर विक्रम सिंह

राजोरी की आतंकी घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया-दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं...अगर बातचीत से यह सुलझाया नहीं गया, तो हमारा हाल वही होगा, जो गाजा फलस्तीन का हो रहा है। अब कौन-सी वार्ता होनी है? पाकिस्तान की तो शर्त है कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक बात नहीं होगी। यह बहाल होना नहीं है, तो स्पष्ट है कि वार्ता भी नहीं होनी है। चाहे महबूबा मुफ्ती हों या फारूक अब्दुल्ला, ये सब पाकिस्तान से वार्ताओं के बड़े पैरोकार हैं। फर्ज करें कि वार्ताएं हुईं भी, तो पाकिस्तान 370 की बहाली के बाद कश्मीर घाटी का इलाका तो अवश्य चाहेगा। लेकिन अब कश्मीर घाटी वार्ता की मेज पर है ही नहीं। वहां तो हमारा एकमात्र मुद्दा पीओके है। इसलिए अब पुराने मुद्दों की दृष्टि से वार्ताओं की कोई साझा भूमि बची ही नहीं है।

दरअसल भारत-पाकिस्तान में विवाद की स्थितियां अब तक शेख अब्दुल्ला परिवार की सत्ता संभावनाएं बनाए रखती रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी बाद में इसी पाकपरस्त क्लब में शामिल हो गए। शेख अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षा एक आजाद खुदमुख्तार कश्मीर की थी। पाकिस्तान के साथ जाना उनके सपने का ही नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व का भी अंत कर देता। इसलिए वह नेहरू-गांधी के अहिंसक सेक्यूलर भारत के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तानी कबाइलियों का पीछा करती भारतीय सेना को अचानक उरी में रोक दिए जाने का उन्हें यह लाभ मिला कि शेख का राजनीतिक विरोधी, पंजाबी डोगरी भाषा-भाषी इलाका भारत से बाहर रह गया और पीओके के रूप में अस्तित्व में आया। यदि वह क्षेत्र भारत में शामिल करा लिया जाता, तो शेख अब्दुल्ला को चुनौतियां मिलने लगतीं।

इसलिए शेख के कश्मीर की सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक था कि सेना वहां से आगे न बढ़े। दूसरा, अनुच्छेद 370 जैसा विशेषाधिकार कश्मीर को दे दिया जाए। चूंकि माउंटबेटन ने नेहरू से जनमत संग्रह की घोषणा करा दी थी, तो शेख अब्दुल्ला की बातों को मानने की मजबूरी हो गई थी, जिसके चलते अनुच्छेद 370 का जन्म हुआ। हालांकि संविधान सभा में इसका विरोध भी हुआ। कश्मीर की पहचान व विशेषाधिकार के प्रतीक के रूप में अनुच्छेद 370 वह आधार बना, जिसने वहां अलगाववादी सोच को एक राजनीतिक आधार दे दिया। अब्दुल्ला परिवार व अलगाववादियों, दोनों के लिए इस विशेषाधिकार की रक्षा करना लक्ष्य हो गया।

इसीलिए 370 के निष्प्रभावी हो जाने का दर्द इन नेताओं को आज भी बहुत सालता है। बहरहाल, विशेषाधिकार तो चला ही गया, लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से मानचित्र पर दिख रहा वह विस्तार भी गायब हो गया है। जम्मू प्रसन्न है, सत्ता की आहटें सुन रहा है। इसलिए कश्मीर की शांति, विकास व रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन की खुशहाली उन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वे यहां गाजा की कल्पना करके उसमें भूत देख रहे हैं।

दूसरी ओर, पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन परवान चढ़ रहा है। अलगाववादी सोच के लिए दूसरी बड़ी समस्या पीओके की वापसी की संभावनाएं भी हैं। यदि ऐसा संभव हुआ, तो कश्मीर की राजनीति में कश्मीर घाटी के वर्चस्व का सूरज स्थायी रूप से डूब जाएगा। यह एक बड़ी चिंता शेख अब्दुल्ला व मुफ्ती मोहम्मद सईद की सोच व उनके वारिसों की है।

पंचायत चुनावों के बाद कश्मीर में स्थानीय जमीनी नेतृत्व की नई पौध विकसित हो रही है। उनके पास आज वे विकल्प हैं, जो पहले कभी नहीं थे। संपूर्ण भारत आज एक विशाल संभावना है। तो विशेषाधिकारों के पुराने सुविधाजीवी, अलगाववपरस्त माहौल में पली-बढ़ी वह राजनीतिक पीढ़ी आज संकट में है। बीत रहे वर्ष 2023 के साथ उनके ये निराशावादी उद्गार व पाकिस्तान से वार्ताओं का पुराना राग एक शोकगीत से अधिक और कुछ नहीं है।

राजनीति का सालभर का लेखा-जोखा

नईदिल्ली। भारतीय राजनीति की परिपाटी कुछ ऐसी है कि यहां लगभग हर वर्ष चुनावी मौसम बना रहता है। लोकसभा चुनाव से देश का सामना भले ही पांच वर्षों में एक बार होता हो, परंतु सभी राज्यों के चुनाव एक ही समय हों, ऐसी व्यवस्था अभी बनी नहीं है। सो हर वर्ष किसी न किसी राज्य को चुनाव में उतरना ही पड़ता है। इस वर्ष भी देश के अनेक राज्यों में विधानसभा के लिए मतदान हुआ और राज्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। कर्नाटक और तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सरकार बनायी वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में विजय दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि राजनीति की बिसात पर उसका पलड़ा कितना भारी है। उत्तर भारत के इन तीनों राज्यों में हुए चुनाव में मोदी का करिश्मा अपने चरम पर दिखा। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के चुनाव परिणाम भी इस बार लीक से हटकर रहे। विपक्ष भी एकजुट हुआ और 2024 चुनाव के लिए उसने एक गठबंधन बनाया।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के खेल के सबसे आकर्षक चेहरे हैं। उनकी लोकप्रियता ने राजनीति के अनेक दिग्गजों को दूर कहीं पीछे छोड़ दिया है। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए चुनाव में मोदी का यही आकर्षण मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। इन तीनों राज्यों में भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किये बिना ही चुनाव मैदान में उतरी थी। तीनों ही राज्यों में पूरा चुनाव अभियान प्रधानमंत्री मोदी के ही इर्द-गिर्द घूमता रहा। यह मोदी पर भरोसा ही था कि अपनी योजनाओं के कारण खासे लोकप्रिय व सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है नारे के साथ मोदी ने राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इस राज्य में अनेक रैलियां और रोड शोज किये और बड़ी जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने प्रयोग किया। वह मोदी के करिश्मे के भरोसे बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी और विजयी होकर निकली। राजस्थान में तो कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर बतायी जा रही थी। यहां कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत ने कमान संभाली थी, जबकि भाजपा ने मुख्यमंत्री के लिए किसी चेहरे को आगे नहीं किया था। इस भरोसे के साथ कि मोदी है तो जीत मुमकिन है। यहां भी मोदी भरोसे पर खरे उतरे। नतीजा, चुनाव में विजय के रूप में सामने आया।

हिंदी पट्टी का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के 230 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज कर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। भाजपा जहां 48.55 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 163 सीटें जीतने में सफल रही, वहीं 40.40 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गयी। भारत आदिवासी पार्टी को एक सीट मिली। पिछले चुनाव में दो सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल सकी। वर्ष 2018 की तुलना में इस बार भाजपा को 54 सीटें अधिक प्राप्त हुईं, जबकि कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। चुनावी पंडितों को जितना आश्चर्य राज्य में भाजपा की जीत से हुआ, उतना ही आश्चर्य नये चेहरे, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने से हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान खासे लोकप्रिय रहे हैं।

मोदी की गारंटी नारे के साथ छत्तीसगढ़ में जिस चुनाव अभियान को भाजपा ने परवान चढ़ाया, उसने यहां की सरकार ही बदल दी। विधानसभा की 90 सीटों के

लिए दो चरणों में हुए मतदान में जनता ने भाजपा पर भरपूर प्यार लुटाया। परिणाम, पिछले चुनाव में कांग्रेस से बुरी तरह मात खायी भाजपा को इस बार 54 सीटें हासिल हुईं। इस तरह भाजपा को 2018 की तुलना में 39 सीटों का लाभ हुआ। जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस 33 सीटों की हानि के साथ मात्र 35 सीटों पर सिमट गयी। एक सीट अन्य के खाते में गयी। चुनाव में भाजपा को जहां 46.27 प्रतिशत मत मिला, वहीं कांग्रेस को 42.23 प्रतिशत। सभी कयासों को धत्ता बताते हुए भाजपा ने नये चेहरे विष्णु देव साय को राज्य की कमान सौंपी।

राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 के लिए पिछले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अपनी सरकार गंवानी पड़ी। भाजपा ने जहां 41.69 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 115 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 69 सीटों (39।53 प्रतिशत वोट शेयर) के साथ कांग्रेस बहुमत से काफी पीछे रह गयी। भारत आदिवासी पार्टी ने तीन, बसपा ने दो और अन्य ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते। पिछले चुनाव की तुलना में जहां भाजपा को 42 सीटों का लाभ हुआ, वहीं कांग्रेस को 30, बसपा को चार और अन्य को आठ सीटों की हानि उठानी पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले भजन लाल शर्मा राज्य के नये मुख्यमंत्री बनाये गये।

तेलंगाना के 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस वर्ष नवंबर में चुनाव हुआ। जिसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को सत्ता से बाहर कर दिया। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नये राज्य बनने के समय से ही तेलंगाना राष्ट्र समिति (अब भारत राष्ट्र समिति) यहां शासन कर रही थी। परंतु बीत नौ वर्षों की सत्ता विरोधी लहर बीआरएस की कल्याणकारी योजनाओं पर भारी पड़ी और उसे महज 39 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया। इस तरह उसे पहली बार राज्य में सत्तारूढ़ होने का अवसर मिला। रेवंत रेड्डी राज्य के नये मुख्यमंत्री बने। चुनाव में भाजपा को जहां आठ सीटें मिलीं, वहीं एआईएमआईएम को सात व कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई को एक सीट मिली। इस चुनाव में कांग्रेस को 45 सीटों का लाभ हुआ और भाजपा को सात सीटों का। बीआरस को 49 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा।

कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए इस वर्ष मई में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वर्ष 2018 के 80 सीटों के उलट इस बार कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और राज्य में अकेले दम सरकार बनाने में सफल रही। जबकि 2018 में 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही भाजपा महज 66 सीटों पर सिमट गयी। वहीं पिछले चुनाव में 37 सीटें जीत किंगमेकर बनने वाली जेडी (एस) महज 19 सीटें ही जीत सकी। अन्य दलों ने चार सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव की तुलना में इस वर्ष जहां कांग्रेस को 55 सीटों का लाभ हुआ, तो अन्य को एक सीट का। भाजपा को 38 और जेडी (एस) को 18 सीटों की हानि उठानी पड़ी। कांग्रेस के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 1989 चुनाव के बाद से पहली बार उसने न केवल इतनी बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि सर्वाधिक वोट शेयर (43.88 प्रतिशत) भी प्राप्त किया। सिद्धारमैया राज्य के मुख्यमंत्री बने।

भारतीय कूटनीति के लिहाज से साल 2023 भाग्यशाली सितारा साबित हुआ और जी-20 देश की इस साल की कूटनीतिक उपलब्धि रही। अपनी जी 20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और परिणामी देशों को मेज के चारों ओर इकट्ठा करने और दुनिया से संबंधित सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा करने, सहमत होने में सक्षम था। जी-20 नेताओं का 18वां शिखर सम्मेलन नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत ने जी20 के स्वरूप को बदल कर जी21 कर दिया। भारत ने विश्वगुरु की तरह दुनिया को राह दिखायी और सभी को साथ लेकर चला भी गया। जी20 समिट में ही भारत ने स्पाइस रूट का एलान कर दिया। भारत से यूरोप तक जिस ट्रेड रूट को बनाने की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने पेश की है, वह पश्चिम एशिया से होकर ही गुजरेगा।

पुष्पा 2, फ़ाइटर जैसी बड़ी फ़िल्मों ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

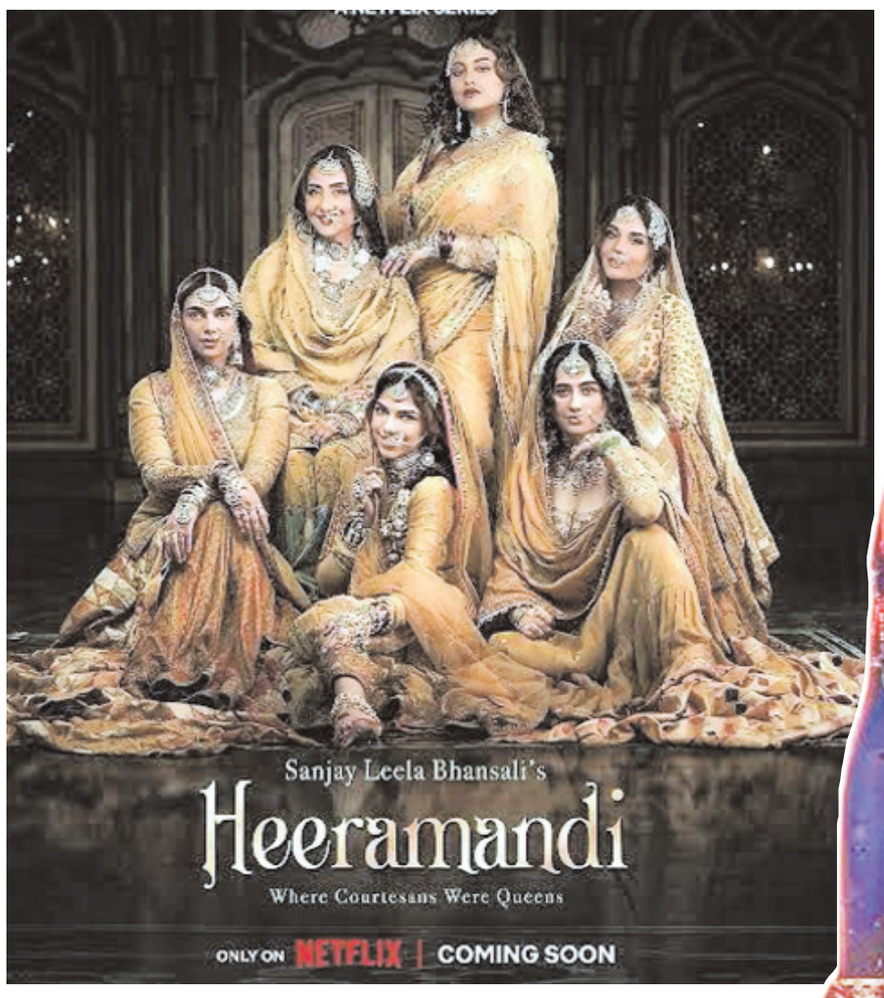

साल 2024 में सिनेमाघरों में कई बड़ी फ़िल्में रिलीज होने वाली है जैसे पुष्पा 2, फ़ाइटर, सिंघम अगेन समेत कई फ़िल्में, जिनका फ़ैंस को बेसब्री से इंतज़ार है । लेकिन इन बड़ी थिएट्रिकल रिलीज के बीच कुछ सीरिज़ ऐसी भी हैं जिनका इंतज़ार किसी बड़ी फ़िल्म से कम नहीं हो रहा है और उनमें शामिल हैं संजय लीला भंसाली की हीरामंडी और रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फ़ोर्स ।

हीरामंडी

संजय लीला भंसाली का ये पीरियड ड्रामा, हीरामंडी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक आकर्षक नरेटिव और शानदार प्रदर्शन का वादा करता है। ये उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो इतिहास से जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और भंसाली के स्टोरीटेलिंग के दीवाने है। यह परियोजना खामोशी के बाद मनीषा कोइराला के साथ उनके अगले सहयोग को चिह्नित करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संजय भंसाली को भारतीय सिनेमा के महान कहानीकारों में गिना जाता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हीरामंडी ग्लबोल दर्शकों के लिए सबसे देसी तरीके से बताई गई भारतीय कहानी का एक और बेहतरीन उदाहरण होगी।

इंडियन पुलिस फोर्स

रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स अब 2024 में ओटीटी पर आएगा । लॉ एंफोर्समेंट की नब्ज पकड़ते हुए, रोहित शेट्टी दर्शकों के लिए उन लोगों की रोमांचक यात्रा और सीटी बजाने वाले पल लाएंगे जो रक्षा और सेवा करते हैं।सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय स्टारर इंडियन पुलिस फ़ोर्स का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है ।

पुष्पा 2

ब्लॉकबस्टर हिट, पुष्पा का सीक्वल, पुष्पा 2 और ज्यादा एक्शन, ड्रामा और अल्लू अर्जुन के जादुई प्रदर्शन के अपने वादे के साथ जबरदस्त चर्चा पैदा कर रहा है, जिससे प्रशंसक उत्सुकता से दिन गिन रहे हैं। फिल्म के टीज़र और पोस्टर पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा चुके हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुष्पा 2 देश भर के दर्शकों के बीच उसी तरह का हंगामा मचा देगी।

फाइटर

जबरदस्त उम्मीदों और सितारों से भरी कास्ट के साथ, फाइटर 2024 में एक प्रमुख आकर्षण बनने के लिए तैयार है। यह फिल्म दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन के पहले ऑनस्क्रीन सहयोग का प्रतीक है और इसके गाने तो पहले से ही फैन्स के बीच हिट है। फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन एंटरटेनर फिल्म भी है और इसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद, तो ऐसा लगता है कि फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है।

सिंघम अगेन

आइकोनिक सिंघम की वापसी एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार है। अजय देवगन एक निडर कॉप के रूप में अपनी भूमिका में लौट रहे हैं और इस बार उनके साथ रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं, ऐसे में फैन्स न केवल इससे हाई-ऑक्टेन एक्शन, देशभक्ती से भरी कहानी की उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि सुपरस्टार कास्ट की टोली के बीच शानदार नजारें की भी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये रोहित शेट्टी की आइकोनिक फ्रेंचाइजी है।

मैरी क्रिसमस

एक दिलचस्प कास्टिंग जिसने हमारे क्रिसमस को और भी खुशनुमा बना दिया, श्रीराम राघवन निर्देशित इस फिल्म में एक दिलचस्प कास्टिंग है जिसमें कैटरीना कैफ विजय सेतुपति के साथ काम कर रही हैं। ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे आने पर मजबूर कर दिया है और हम 2024 में इस मनोरंजक फिल्म से राघवन की सिगनेचर थ्रिलिंग स्टोरीटेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं।

पत्नी लिन लैशराम संग वेकेशन पर रवाना हुए रणदीप हुड्डा

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम बी-टाउन इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। शादी के बाद से ही ये कपल चर्चा में बना है। आए दिन कपल से जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। हाल ही में रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जैसे कि साल 2023 खत्म होने वाला है ऐसे में नए साल 2024 का जश्न मनाने के लिए कपल वेकेशन के लिए रवाना हुआ है। एयरपोर्ट पर कपल का स्टाइलिश लुक देखने को मिल रहा है। लुक की बात करें तो व्हाइट क्रॉप टॉप, व्हाइट पैंट और पेस्टल ग्रीन शर्ट में लिन बेहद ही स्टाइलिश लग रही हैं। उनके लुक ने हर किसी का दिल जीत लिया। अपने एयरपोर्ट लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राउन कलर का टोट बैग कैरी किया था। वहीं रणदीप हुड्डा हल्के पेस्टल रंग की शर्ट और जैतून हरे रंग की पैंट में हैंडसम दिखे। उन्होंने काले धूप का चश्मा और भूरे रंग की टोपी पहनकर अपने लुक को पूरा किया। कपल ने एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में पोज दिए।

दुल्हन शूरा संग हनीमून पर रवाना हुए अरबाज खान

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने साल 2017 में मलाइका अरोड़ा से तलाक लिया था। अब 7 साल बाद अरबाज खान ने दूसरी शादी रचाई। अरबाज खान ने 24 दिसंबर को मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से निकाह रचाया। निकाह से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थीं। अब दोनों वेकेशन के लिए रवाना हो गए हैं। सेलिब्रेशन डबल है, नए साल के जश्न के साथ-साथ हनीमून के लिए भी दोनों साथ निकल चुके हैं । शनिवार सुबह इस कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। शूरा ने कैजुअल और आरामदायक आउटफिट को चुना। लुक की बात करें तो हसीना ग्रे टॉप और मैचिंग पैंट में स्टाइलिश दिखीं। उन्होंने इस आउटफिट को व्हाइट स्नीकर्स, ग्रे बैग और ब्लैक बेसबॉल कैप के साथ पेयर किया। इस दौरान अरबाज खान डेनिम जींस और ब्लैक टी-शर्ट में हैंडसम दिखे। अरबाज खान और शूरा खान हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर नजर आए। शूरा से पहले अरबाज खान मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे थे।

तोड़ी जाएगी समंदर किनारे मौजूद आमिर की बिल्डिंग, घर मालिकों को मिलेंगे अल्ट्रा-लक्जरी फ्लैट्स

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी लाडली आइरा खान की शादी की तैयारियों में बिजी हैं। खबरों की मानें तो आइरा 3 जनवरी को दुल्हन बनने जा रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि आमिर की पॉश बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी चल रही है। ये तोड़फोड़ किसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर नहीं हो रही बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। बताया जा रहा है कि मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड बांद्रा के पॉश पाली हिल इलाके की एक बिल्डिंग की रीडेवलप करने की तैयारी है जिसमें की सारे फ्लैट्स आमिर खान के हैं। ये पॉश बिल्डिंग समंदर किनारे बांद्रा में मौजूद है जिसमें लोगों के घर 37,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैले हैं। अब इसके रीडेवलपमेंट का काम 2024 के मिड में शुरू होगा। दरअसल ये प्रॉपर्टी विर्गो सीएचएस लिमिटेड की है जिसमें दो विंग बेला विस्टा और मरीन शामिल हैं। इस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 24 फ्लैट हैं जिनमें से 9 फ्लैट के मालिक आमिर खान हैं। इस बिल्डिंग में लगभग 50,000 स्क्वायर फीट के सेल कंपोनेंट के साथ अल्ट्रा-लक्जरी फ्लैट होंगे, जिसका लक्ष्य करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू होगा। एक असोसिएट कंपनी की मदद से एमआईसीएल इसके रिडेवलपमेंट की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि रिडेवलपमेंट के बाद फ्लैट्स के मालिकों को अब करीब 55-60 पर्सेंट एक्स्ट्रा एरिया के साथ बड़े फ्लैट्स मिलेंगे। पाली हिल में बनी इस बिल्डिंग के रिडेवलपमेंट के बाद 4 और 5 बीएचके वाले हर एक फ्लैट की कीमत 125 हजार पर स्क्वायर फीट की कीमत पार करने की संभावना है।

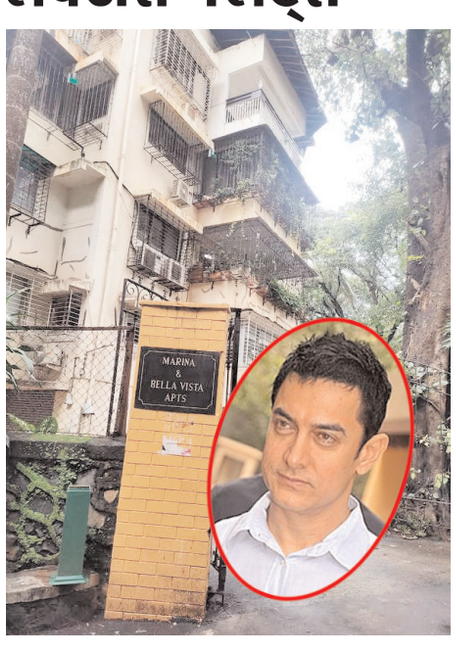

संजू के बाद एक और फिल्म के लिए फिर साथ आएंगे रणबीर और हिरानी

2018 की फिल्म संजू में रणबीर कपूर के साथ काम करने वाले राजकुमार हिरानी ने इंडिया टुडे के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि वह रणबीर के साथ निश्चित रूप से एक और फिल्म करना पसंद करेंगे। अभिनेता, जो वर्तमान में एनिमल की सफलता पर सवार हैं, ने कथित तौर पर भारत में रु. 541.87 करोड़ की कमाई की और 1 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से दुनिया भर में ?885 करोड़ की कमाई की।

संजू में रणबीर कपूर के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता ने कहा, रणबीर एक परम प्रिय व्यक्ति हैं। संजू बनाने में हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं निश्चित रूप से उनके साथ एक और फिल्म करना पसंद करूंगा। मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट हैं और हम संपर्क में हैं। तो आइए देखें कि यह कहां जाता है। कभी-कभी, ऐसा होता है कि आप एक विशेष स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं और वह कहीं नहीं जाती है और फिर आप दूसरी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं और वह कुछ बन जाती है। तो हाँ, मैं रणबीर से प्यार करता हूँ।

अभिनेता संजय दत्त पर राजकुमार हिरानी की बायोपिक, जिसका नाम संजू है और जिसमें रणबीर कपूर ने अभिनय किया है, ने भारत में ?342.57 करोड़ की कमाई की और दुनिया भर में ?588.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म में परेश रावल ने संजय के पिता, अभिनेता-राजनेता सुनील दत्त की भूमिका निभाई, जबकि मनीषा कोइराला ने संजय की मां, अभिनेता नरगिस की भूमिका निभाई। स्टार कलाकारों में सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, दीया मिर्जा, विक्की कौशल, जिम सर्भ और अन्य भी शामिल थे।

यह वर्ष उद्योग में फिल्म निर्माता का 20वां वर्ष भी है। उसी का जश्न मनाते हुए, कुछ हफ्ते पहले शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान सहित कई अभिनेताओं ने उन्हें उनकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजी थीं। रणबीर कपूर, जिन्होंने पहले संजू में हिरानी के साथ काम किया था, ने साझा किया, फिल्म उद्योग में, आपके साथ काम करने का सौभाग्य पाकर, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इससे बेहतर कोई इंसान नहीं है - इससे अधिक निस्वार्थ, अच्छा और कड़ी मेहनत करने वाला।

आमिर की बेटी इरा की मुंबई में नुपुर शिखारे से होगी शादी

आमिर खान की बेटी इरा की शादी मुंबई में नुपुर शिखारे से होने वाली है, जिसके बाद जयपुर में रिसेप्शन होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इरा खान और नुपुर शिखारे की अंतरंग शादी मुंबई में होगी, जिसके बाद कोर्ट मैरिज होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद यह जोड़ा जयपुर में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन करेगा, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगी। आमिर खान की बेटी इरा खान और उनके मंगेतर नुपुर शिखारे 3 जनवरी, 2024 को शादी करने वाले हैं। इंटरनेट पर कई खबरें चल रही थीं कि दोनों एक साधारण महाराष्ट्रीयन शैली में शादी करेंगे, लेकिन अब आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी अंतरंग शादी मुंबई में होगी, जिसके बाद कोर्ट मैरिज होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद यह जोड़ा जयपुर में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन करेगा, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगी। दोनों ने 2022 में इटली में सगाई की, जिसके बाद उन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के लिए मुंबई में एक सगाई पार्टी की मेजबानी की। कुछ दिन पहले शादी का जश्न शुरू हुआ था।

जिसमें जोड़े के परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। अभिनेत्री मिथिला पालकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी स्टोरीज पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें दूल्हा और दुल्हन के साथ देखा जा सकता है। एक अन्य इंस्टा स्टोरीज़ में, इरा को अपने बॉयफ्रेंड नुपुर के साथ मिथिला और परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ पोज़ देते देखा जा सकता है। समारोह के लिए, इरा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि नुपुर ने काले पायजामा के साथ एक लंबा लाल कुर्ता पहना था। इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में, इरा ने अपने मंगेतर नुपुर शिखारे के लिए एक सराहना पोस्ट साझा की थी और उन्हें अपना %अभिन्न हिस्सा% कहा था। पोस्ट में, उन्होंने अपनी सगाई के दिन की तस्वीरों की एक श्रृंखला भी साझा की। तस्वीरों के साथ, उसने अपने साथी के लिए एक लंबा नोट लिखा और लिखा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पर्याप्त बता पा रही हूं या आपके प्रति अपने प्यार और प्रशंसा को व्यक्त करने में सक्षम हूं। मैं जानती हूं कि जब हम गले मिलते हैं तो आप और मैं दोनों इसे महसूस करते हैं। आप पर्यावरण का एक अभिन्न अंग और परिवर्तनशील व्यक्ति हैं जिसने मुझे बढ़ने में मदद की है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी इसकी सीमा जान पाएंगे और न ही मैं इसे स्पष्ट कर पाऊंगी। और आप मेरे जीवन में जो कुछ भी लाते हैं उसका दूसरा पक्ष अभी भी है जो व्यक्तिगत विकास से परे है, और वह बाहर है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ललन सिंह चुप नहीं बैठेंगे अलर्ट रहें नीतीश : सुशील

पटना। ललन सिंह के जनता दल (यूनाइटेड) के शीर्ष पद से हटने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक खेल की शुरुआत है और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि सिंह जल्द ही अपमान का बदला लेंगे और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो सकते हैं। बस रुको और देखो। सिंह का बाहर जाना एक बड़े खेल की शुरुआत है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है. हालाँकि, सिंह चुप नहीं बैठेंगे। वह जल्द ही अपमान का बदला लेंगे, वह राजद से भी हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सिंह को उनके पद से हटा दिया जाएगा। सिंह ने कथित तौर पर राजद प्रमुख लालू यादव के साथ मिलकर मिश्री लाल यादव को सीएम पद के लिए समर्थन देने की साजिश रची थी और 12 विधायकों का विश्वास जीता था।

ईडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सातवां समन

रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में पीएमएलके के तहत सातवां समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें इस मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। मंगलवार को सीएम सोरेन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुमका के लिए रवाना हुए, इसी बीच अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोरेन को नया समन जारी किया था। जानकारी के मुताबिक, सोरेन को मंगलवार सुबह 11 बजे हिनू इलाके में संघीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री का मंगलवार को दुमका में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था।

राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने भाजपा पर कसा तंज

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर के राजनीतिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के लिए एकमात्र चीज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित करना है। राउत की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के नदी किनारे के शहर की यात्रा से पहले आई है, जहां उनका कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करने का कार्यक्रम है। अपने बयान में राउत ने कहा कि अब बस यही बाकी है कि बीजेपी यह घोषणा करेगी कि चुनाव में भगवान राम उनके उम्मीदवार होंगे। भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। राउत ने पहले कहा था कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन एक भाजपा कार्यक्रम है, न कि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम। भाजपा इस समारोह के लिए खूब रैलियां और प्रचार कर रही है लेकिन इसमें पवित्रता कहां है।

विपश्यना ध्यान केंद्र से वापस लौटे सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को विपश्यना ध्यान केंद्र से निकले हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापिस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। इस दौरान सीएम केजरीवाल पहले से तय विपश्यना कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए थे। वह विपश्यना ध्यान केंद्र में 30 दिसंबर तक मौजूद रहे। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धति है, जिसका अभ्यास करने वाले लोग कुछ समय के लिए देश-दुनिया से कट जाते हैं और एकांतवास में रहते हैं। इसे एक तरह का योगाभ्यास भी कहा जा सकता है।

हिंदुत्व और हिंदू अलग-अलग, मैं हिंदू हूं : सिद्धारमैया

बेंगलुरु। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला किया। बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा, नरम हिंदुत्व अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों से समझौता किए बिना उदारवादी हिंदुओं के वोट हासिल करने की भाजपा की एक राजनीतिक रणनीति है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हिंदुत्व है। मैं एक हिंदू हूं. हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है। उनका यह बयान 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से पहले आया है। अपने जीवन से अंतर्दृष्टि साझा करते हुए, सिद्धारमैया ने आगे कहा कि वह अपने गांव में भजनों के लिए जाते थे और कहते थे, हम भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा प्रचारित हिंदुत्व फर्जी है। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पार्टी की भागीदारी को दोहराते हुए उन्होंने कहा, भाजपा, जनसंघ, आरएसएस और संघ परिवार के एक भी व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी।

अयोध्या में बोले प्रधानमंत्री- 22 जनवरी का पूरी दुनिया कर रही इंतजार

विकास और विरासत की साझा ताकत भारत को ले जाएगी आगे: मोदी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या दौरे पर थे। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज प्रधानमंत्री ने रामनगरी में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, दो अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री का एक लंबा रोड शो भी हुआ। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या में विकास की भव्यता दिखेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्यावासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण-कण और भारत के जन-जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। 1943 में आज के ही दिन नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहरा कर भारत की आजादी का जयघोष किया था। उन्होंने कहा कि आजदी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज यहां 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे।

मोदी ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है, तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत, पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज का भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। यहां श्रीराम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। उन्होंने कहा कि आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्रीराम के कृतित्व से परिचित करवाया।

प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन 'अयोध्या धाम' का उद्घाटन किया और दो नयी अमृत भारत व छह नयी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय अयोध्या दौरे पर शनिवार सुबह यहां पहुंचे। वह अयोध्या हवाई अड्डे से एक रोड शो करते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख?यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण 240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में पहचाने जाने वाला तीन मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, अमानती सामान घर, बाल देखभाल कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बयान के अनुसार, स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। प्रधानमंत्री ने देश में सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की नयी श्रेणी 'अमृत भारत एक्सप्रेस' को हरी झंडी भी दिखायी। अमृत भारत ट्रेन एक 'एलएचबी पुश-पुल' ट्रेन है जिसमें गैर वातानुकूलित बोगियां हैं। इसमें रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, बेहतर सामान रैक, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइट, सीसीटीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोदी ने दो नयी अमृत भारत ट्रेन दरभंगा-अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनस (बेंगलुरु) अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखायी।

इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस की सीट-बंटवारे की योजना

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में हो रही उलझन

नईदिल्ली। विपक्षी इंडिया गुट की हालिया बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का फैसला किया गया था। दिल्ली में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य फोकस सीट-बंटवारे पर आम सहमति बनाने पर था, लेकिन अब यह कांग्रेस के लिए एक कठिन काम लगता है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अब, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अकेले चुनाव लड़ने की योजना पर जोर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) ने 23 सीटों की मांग की है, जिससे चर्चा में बाधा आ रही है।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में भारतीय गुट के सहयोगी कांग्रेस की सीट-बंटवारे की योजना को स्पष्ट रूप से रोक रहे हैं। ममता बनर्जी ने गुरुवार को घोषणा की कि टीएमसी 2024 का लोकसभा चुनाव राज्य में अकेले लड़ेगी, जबकि इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगा। राज्य में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का ब्लॉक पूरे देश में होगा। बंगाल में टीएमसी लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। याद रखें, बंगाल में केवल टीएमसी ही बीजेपी को सबक सिखा सकती है, कोई अन्य पार्टी नहीं।

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 48 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली. 2019 का चुनाव भी शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था. बीजेपी ने 23 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटें जीतीं।

राहुल की यात्रा के रूट में अरुणाचल के न होने पर भड़के भाजपा नेता

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हाल ही में दी। तभी से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस बीच, राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने यात्रा के बदले मार्ग पर चिंता जताई है। उन्होंने साल 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के कांग्रेस के फैसले सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और साथ ही जयराम रमेश से जवाब मांगा। जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर जयराम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल प्रदेश पर जयराम रमेश के विचारों को पढ़ना अजीब लगता है। अब यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री के रूप में वह राज्य में सभी मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करना चाहते थे और किसी भी नई परियोजना को रोकना चाहते थे। रमेश ने तब जोर देकर कहा था कि भारत अपने दम पर बांधों का निर्माण करने में सक्षम नहीं होगा और उसे राज्य में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में चीन को शामिल करना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

एआईटीए को डेविस कप के लिये पाकिस्तान दौरे को मंजूरी मिलने की उम्मीद

नईदिल्ली। भारतीय टीम को आगामी डेविस कप टेनिस मुकाबले के लिये पाकिस्तान जाने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) ने शनिवार को यह जानकारी दी। एआईटीए ने हाल ही में खेल मंत्रालय से सलाह मांगी थी कि क्या वे तीन और चार फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले विश्व ग्रुप वन प्लेआफ के लिये टीम भेज सकते हैं।

एआईटीए महासचिव अनिल धूपर ने पीटीआई से कहा ,'' हमें अभी तक लिखित में मंजूरी नहीं मिली है लेकिन जल्दी ही मिल जायेगी। हमें बताया गया है कि चूंकि यह द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है और आईटीए इसका आयोजन कर रहा है तो सरकार ऐसे टूर्नामेंटों में दखल नहीं देती।'' उन्होंने कहा ,'' इसकी प्रक्रिया है। खेल मंत्रालय ने विदेश और गृह मंत्रालय को अनुरोध भेज दिया है और उनकी राय के बाद ही अंतिम फैसला लिया जायेगा। हमें जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हम मुकाबले और यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।''

इस बीच पाकिस्तान टेनिस महासंघ (पीटीएफ) ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले डेविस कप मुकाबले में एआईटीए के खिलाड़ियों और अधिकारियों की भागीदारी को लेकर उसे अंतिम पुष्टि का इंतजार है। पीटीएफ अध्यक्ष सलीम सैफुल्लाह ने कहा ,'' एआईटीएफ ने हमें वीजा के लिये 11 अधिकारियों और सात खिलाड़ियों की सूची भेजी है। हमें उनके आने की अंतिम पुष्टि का इंतजार है।'' उन्होंने कहा ,'' एआईटीए ने कहा है कि उनकी सरकार से पाकिस्तान यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद ही वे पुष्टि करेंगे।'' उन्होंने बताया कि सूची में एआईटीए अध्यक्ष अनिल जैन और सचिव अनिल धूपर के भी नाम हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

अमृत भारत का किराया सामान्य ट्रेन के किराये से 17% ज्यादा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। इस ट्रेन में सफर करना सामान्य ट्रेनों की तुलना में 17 प्रतिशत महंगा है लेकिन यह ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। रेलवे बोर्ड ने अपने अलग-अलग जोन्स को बताया है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में एक किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गंतव्यों के लिए न्यूनतम किराया 35 रुपये है। इसमें आरक्षण शुल्क और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। रेलवे ने अमृत भारत ट्रेनों के किराया ढांचे पर एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया है। रेलवे ने इस सर्कुलर के साथ ही द्वितीय श्रेणी (सेकेंड क्लास) और शयनयान श्रेणी (स्लीपर क्लास) के यात्रियों के लिए दूरी और टिकट की कीमतों से जुड़ी एक किराया तालिका भी साझा किया है। अमृत भारत ट्रेन में केवल द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के डिब्बे होंगे।

नए साल से बंद हो सकती है आपकी यूपीआई आईडी

नईदिल्ली। निफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 जनवरी 2024 से आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है। ऐसा होने पर आप न तो पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे और न ही रिसीव कर पाएंगे। यूपीआई आईडी बंद होने को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 7 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें जानकारी दी थी कि 31 दिसंबर 2023 के बाद कई यूपीआई यूजर्स की आईडी बंद हो सकती है। ऐसे में लोगों को पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एनपीसीआई के द्वारा जारी किए सर्कुलर के मुताबिक, जिन यूजर्स ने पिछले एक साल से अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है या जिनकी आईडी इनएक्टिव है, उन सभी की आईडी 1 जनवरी 2024 से काम नहीं करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने विभिन्न अवधि की सावधि जमाओं (एफडी) की ब्याज दरों को 1.25 प्रतिशत तक बढ़ाया है। इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी सावधि जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई थीं। बीओबी ने एक बयान में कहा, विभिन्न अवधि की दो करोड़ रुपये तक की सावधि जमाओं पर ब्याज दर 0.01 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। नयी दरें 29 दिसंबर, 2023 से लागू हैं। बयान के मुताबिक सर्वाधिक 1.25 प्रतिशत वृद्धि 7-14 दिनों की अवधि में की गई है। इन जमाओं के लिए ब्याज दर तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 4.25 प्रतिशत कर दी गई है। इसके बाद 15-45 दिन की पूर्ण अवधि के लिए ब्याज दर एक प्रतिशत बढ़कर 4.50 प्रतिशत कर दी गई है।

एन्नोर विनिर्माण इकाई में अमोनिया सुरक्षा प्रणालियां मजबूत

नईदिल्ली। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की चेन्नई स्थित उर्वरक विनिर्माण इकाई में अमोनिया सुरक्षा प्रणालियां किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए काफी 'मजबूत' हैं और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित पाइपलाइन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय तकनीकी दल (समिति) ने 27 दिसंबर को अमोनिया प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस दल में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईआईटी शिक्षाविद् और पर्यावरण एजेंसियों के विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल थे। इससे पहले उत्तरी चेन्नई के एन्नोर में स्थित कंपनी की उर्वरक विनिर्माण इकाई से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था।

बढ़ती अर्थव्यवस्था ने बढ़ाईं उम्मीदें

अभिजीत मुखोपाध्याय

बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में लगातार वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगा था कि 2023 वैश्विक मंदी का साल होगा। पहले महामारी और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध एवं पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आते अवरोध से भी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की आशंका बनी रही, लेकिन साल के अंत तक ऐसी आशंकाएं गलत साबित हुईं। इस वर्ष सकल वैश्विक उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। दुनिया भर में रोजगार बाजार लगातार बढ़ोतरी हुई, हालांकि इसकी दर बहुत अधिक नहीं रही। आम तौर पर मुद्रास्फीति भी घटती गयी है और विश्वभर के शेयर बाजारों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कहा जा सकता है कि वैश्विक मंदी की आशंकाएं बढ़ा-चढ़ा कर बतायी जा रही थीं और सबसे बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि जहां कुछ देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी रही, वहीं कुछ देशों का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा।

मूल्य प्रबंधन, सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में वृद्धि, रोजगार बढ़ाने और शेयरों के दाम के मामलों में यूनान ने लगातार दूसरे साल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले तक यूनानी अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम चिंताएं जतायी जा रही थीं। इसी तरह दक्षिण कोरिया और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन भी उत्साहजनक रहा। दिलचस्प है कि कुछ अन्य अच्छे प्रदर्शन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देशों में देखने को मिले। कनाडा और चिली शीर्ष के तीन

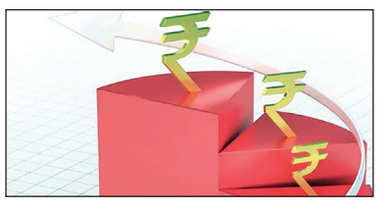

देशों से बहुत पीछे नहीं हैं। सबसे निराशाजनक स्थिति उत्तरी यूरोप के देशों में रही, जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा स्रोतों के दाम में बड़ी वृद्धि तथा चीन से आयातित कारों से प्रतिस्पर्धा जैसे कारणों से जर्मनी की स्थिति खराब है। ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय संघ से अलग होने के परिणामों से जूझ रहा है। माना जा रहा था कि यूरो जोन से निकलना ब्रिटेन के लिए लाभप्रद नहीं होगा और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। कुछ अन्य यूरोपीय देश भी यूक्रेन युद्ध से महंगे हुए तेल और गैस के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एस्टोनिया ऐसा ही एक देश है। रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर फिनलैंड की अर्थव्यवस्था भी संकटग्रस्त है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में अब भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में आर्थिक वृद्धि अच्छी रही, पर दुनिया भर में उत्पादकता बढ़ोतरी कमजोर रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था उस गति से नहीं बढ़ पा रही है, जैसी उसकी क्षमता है। कुछ देशों में रोजगार जरूर बढ़े, पर आंकड़े शून्य से कुछ ही ऊपर हैं। इस कारण साल के शुरू में श्रम बाजार जैसे ठिठका हुआ था, वही हाल साल के अंत में भी है। चीन की अर्थव्यवस्था में कमी आने से भी वैश्विक वृद्धि प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद भी चीन में जीडीपी की दर कमतर है और रोजगार वृद्धि में भी गिरावट आयी है। इसी बीच वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने औसतन 7.7 प्रतिशत की वृद्धि कर कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। लागत खर्च में कमी तथा कॉर्पोरेट मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ ऐसी वृद्धि अगले कुछ तिमाहियों तक बनी रहेगी, लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय है। हालांकि हालिया आंकड़े सुधार को इंगित कर रहे हैं, पर रिजर्व बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी तेजी निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का एक कारण हो सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक को दामों पर, खास कर खाद्य और ऊर्जा में, नजर रखनी होगी। मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे से कुछ अधिक बनी रह सकती है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजट में अनुमानित राजस्व के आधे से अधिक हिस्से को हासिल कर लिया है तथा खर्च को भी आधे से कम के स्तर पर रखा गया है।

कही-सुनी

रवि भोई

छत्तीसगढ़ की सरकार पर संघ की बारीक नजर

कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पर आरएसएस के पदाधिकारियों की बारीक नजर बनी हुई है। खबर है कि भाजपा के एक नए नवेले मंत्री ने सार्वजानिक तौर से सरकार गठन का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। इस पर संघ के पदाधिकारियों की भौहें तन गई और मंत्री को सीमा में रहने का संदेश भिजवा दिया। कहते हैं आरएसएस पदाधिकारियों की टेढ़ी नजर के बाद मंत्री जी ने सोशल मीडिया के जरिए क्षमा याचना की। कहते हैं आरएसएस के पदाधिकारियों का साफ़ संदेश है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पदाधिकरियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आई है। चर्चा है कि संघ के पदाधिकारियों ने एक मंत्री को उनके परिवार से जुड़े मामले में क्या रुख अपनाना है, इसकी सलाह और हिदायत दी है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के स्टाफ में किन लोगों को रखा जाएगा, इसका भी निर्धारण संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं। बताते हैं प्रत्येक मंत्री के कार्यालय में संघ से जुड़े एक व्यक्ति की तैनाती होगी, जो समन्वय के साथ नजर रखने का भी काम करेगा। कहते हैं रमन सिंह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री निवास पर संघ के प्रतिनिधि के तौर पर विवेक सक्सेना की पदस्थापना हुई थी।

अमित जोगी का प्लान

कहते हैं जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कोरबा लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर है कि अमित जोगी ने विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को भरपूर साथ दिया। इस अहसान के बदले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमित जोगी को सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी। कहा जा रहा है कि अमित जोगी की कोशिश है कि जोगी कांग्रेस का भाजपा में विलय हो जाय और उन्हें भाजपा कोरबा से उम्मीदवार बना दे। माना जा रहा है कि भाजपा के पास अभी कोरबा के लिए कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है। कोरबा से नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत अभी सांसद हैं। अब देखते हैं अमित जोगी की रणनीति कितनी सफल होती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने वाली जोगी कांग्रेस 2023 में शून्य पर रही।

अब बारी कांग्रेस सचिवों की

कहते हैं कि कांग्रेस की नेता सैलजा को छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव के पद से हटाने के बाद अब सचिवों की बारी है। छत्तीसगढ़ में चंदन यादव, विजय जांगिड़ और सप्तगिरि शंकर उल्का कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं। विजय जांगिड़ तो सैलजा से अटैच थे। सैलजा के जाने के बाद जांगिड़ का जाना तय माना जा रहा है। पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल ने चंदन यादव पर सीधे आरोप लगाया है। इस कारण चंदन यादव पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। सप्तगिरि आदिवासी नेता हैं। सप्तगिरि के प्रभाव से बस्तर में पार्टी

के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस्तर की 12 सीटों में से आठ सीटें कांग्रेस हार गई। 2018 में उसे 11 सीटें मिली थीं।

विभाग बांटने में आखिर देरी क्यों हुई ?

मंत्रियों को शपथ के पूरे आठ दिन बाद विभाग मिल पाया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की शपथ के एक हफ्ते बाद ही मंत्रिमंडल का गठन हो पाया। मंत्रियों के चयन और उन्हें विभाग देने में देरी को लेकर चर्चा गर्म है। कहते हैं पहले भाजपा संगठन पुराने नेताओं को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं था। बताते हैं भाजपा की पहली लिस्ट में पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव और खुशवंत साहेब जैसे विधायकों का नाम था। खबर है कि पुराने नेताओं की नाराजगी से लोकसभा चुनाव में नुकसान के भय के चलते पहले मंत्री रह चुके लोगों को साय कैबिनेट में जगह दी गई। कहा जा रहा है पहले 13 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का प्लान था। दिग्गजों को मनाने के फेर में मत्रियों की शपथ 22 दिसंबर को हो सकी। फिर विभागों के वितरण का आफ्टर इफैक्ट का विश्लेषण करने में ही संघ और भाजपा के बड़े नेताओं को आठ दिन लग गए। कहते हैं विभाग से ज्यादा व्यक्ति मैटर करता है। यह बताना शरू कर दिया है एक मंत्री ने। उन्होंने अपने विभागों की मार्केटिंग शुरू कर यह बताने की कोशिश कर दी है कि उन्हें मिले विभाग उनके कद के अनुरूप हैं।

सरकार के केंद्र में ओपी चौधरी

विष्णुदेव साय की सरकार में ओपी चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए हैं। रामचंद्र सिंहदेव और अमर अग्रवाल के बाद चौधरी राज्य के तीसरे वित्त मंत्री हैं। 2007 के बाद 2018 तक मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा। इसके बाद कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग किसी को नहीं दिया। वित्त विभाग से हर विभाग का वास्ता पड़ता है। बजट आबंटन से फाइल में मंजूरी तक। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बाद ओपी चौधरी सरकार के केंद्र में रहेंगे। ओपी चौधरी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खाली खजाना और कर्ज के बोझ के बीच रास्ता निकालते हुए उन्हें मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए विभागों को पैसा देना होगा। ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने गणित के विद्यार्थी रहे चौधरी कौन सा फार्मूला निकालते हैं, उसका इंतजार है।

कर्म का फल

कहते हैं न जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा ही कुछ एक भाजपा नेता के साथ हो गया। इस भाजपा नेता को साय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बड़े एप्रोच लगे। भाजपा नेता मंत्री बनने की दौड़ में आगे थे, पर पिछला काम उन्हें ले डूबा। खबर है कि नेताजी को उनके अच्छे दिनों में संगठन में कुछ काम सौंपे थे। नेताजी संगठन के मापदंड पर खरे उतरने की जगह बहती गंगा में हाथ धो लिया। पिछले पांच साल में उनका जाति प्रेम भी इस बार उनके मंत्री बनने में रोड़ा बन गया। अब नेताजी वरिष्ठ और अनुभवी होने के बाद भी खाली हाथ रह गए।

चीफ सेक्रेटरी तो बने रहेंगे

कहते हैं चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन भाजपा सरकार में चलते रहेंगे। एक तो अमिताभ जैन ने कांग्रेस मानसिकता के होने की छवि नहीं बनाई, दूसरा उनका कोई विकल्प नहीं है। सुब्रत साहू दौड़ में थे, उन्हें इस सरकार ने साइड लाइन कर दिया है । सुब्रत साहू को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर उनके विभाग फिलहाल यथावत रखे हैं। चर्चा है कि प्रशासनिक फेरबदल

में उनके विभाग बदल दिए जाएंगे। खबर है कि सुब्रत साहू दूसरे विभागों की बैठक में अब नजर नहीं आते। रेणु पिल्ले को भी मुख्य सचिव बनाने के पक्ष में भाजपा नहीं है।

अगला डीजीपी कौन ?

डीजीपी अशोक जुनेजा का बदला जाना तय माना जा रहा है। अशोक जुनेजा के बाद सबसे वरिष्ठ 1990 बैच के आईपीएस राजेश मिश्रा हैं, पर वे अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। राजेश मिश्रा को सेवावृद्धि मिल जाय तो उनका नंबर लग सकता है। राजेश मिश्रा केंद्र सरकार में भी काम कर चुके हैं। भूपेश सरकार में राजेश मिश्रा लूप लाइन में थे। नए डीजीपी के लिए अरुण देव गौतम और पवन देव का नाम भी चर्चा में है। वैसे नई सरकार आने के बाद जुनेजा साहब पुलिस अफसरों की मीटिंग लेकर कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन नदी में पानी काफी बह चुका है। इस कारण लोगों को नई सरकार में नए डीजीपी का इंतजार है।

नहीं टूट रहा पद का मोह

राजनीतिक नियुक्ति वाले पद में कार्यरत एक अफसर का मोह टूट नहीं रहा है। सरकार बदलने के बाद कायदे से उन्हें बोरिया-बिस्तर बांधकर चला जाना चाहिए। नई सरकार उनकी दोबारा ताजपोशी कर दे तो अलग बात है। कहते हैं ये अफसर दोबारा पद पाने के लिए मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। वैसे भाजपा शासन में ये अफसर ऊंचे ओहदे में रह चुके हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। कहते हैं एक अफसर तो बिना विभाग के संविदा में बने हुए हैं और मंत्रालय में अपने नाम से कमरा एलाट हैं। इस अफसर के ऊपर एक जाँच एजेंसी की तलवार लटक रही है।

मोदी जी की गारंटी पूरा करने मनोयोग से जुट जाएं मंत्रीगणः मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मंत्रीगणों को विभागों के आबंटन के पश्चात आज मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी मोदी जी की गारंटी पूरा करने पूरे मनोयोग से जुट जाएं। प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कड़ी मेहनत से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्येय वाक्य है सुशासन का सूर्योदय, इसे चरितार्थ करना है। अगले पांच सालों में मोदी जी द्वारा दी गई सारी गारंटी पूरी करनी है। पूरी पारदर्शिता के साथ आम जनता को इसका लाभ देना है। मोदी जी की गारंटी समाज के सभी वर्गों से संबंधित है और आपको सुनिश्चित करना है कि उनकी गारंटी का जमीनी क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।

छग में 31 नए कोरोना मरीज मिले

रायपुर और रायगढ़ में सबसे ज्यादा केस, एक्टिव केस अब 66

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है. प्रदेश में आज एक ही दिन में कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं. सबसे ज्यादा रायगढ़ में 14 और रायपुर में 10 कोरोना मरीज मिले हैं. छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 66 हो गई है. रायपुर में अभी 15 एक्टिव मरीज हैं. वहीं रायगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या 22, दुर्ग में 12 केस हैं. बस्तर में आज एक मरीज मिले हैं, बस्तर में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है.

देश में 24 घंटे में 797 नए मामले

देश में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 797 नए मामले मिले हैं। बता दें कि यह बीते करीब सात महीने (225 दिन) में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 4091 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से पांच लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना का नया वैरिएंट जेएन.1 का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में गुरुवार तक जेएन.1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। जेएन.1

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी किया नोटिस

रायपुर. सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को पदोन्नति चैनल नहीं बनाए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. गौरतलब है कि प्रदेशभर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में नियमित डाटा एंट्री आपरेटर जो 8-10 साल से पदस्थ हैं. सेवा भर्ती नियम एवं सेवा शर्तें नहीं बनाए जाने के कारण पदोन्नति, समयमान वेतनमान और अन्य लाभ से वंचित हैं. छत्तीसगढ़ शासकीय डाटा एंट्री कंप्यूटर आपरेटर संघ के प्रांतीय संयोजक दिलीप चौरसिया ने बताया कि लगातार पत्राचार/अभ्यावेदन देने के बावजूद सेवा भर्ती नियम एवं सेवा शर्त बनाए जाने के संबंध में पहल नहीं की गई. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सेवा भर्ती नियम एवं सेवा शर्तें तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत पदोन्नत चैनल निर्मित करने एवं अन्य सुसंगत संवैधानिक लाभ के लिए तिरिथ राम, गोवर्धन चेलक, देव प्रकाश साहू, सौरभ पांडेय, राजकुमारी ध्रुव, धनंजय देवांगन, मुकेश सिंह ठाकुर, आकाश शर्मा, परमेश्वर चक्रधारी एवं राजू कुमार जायसवाल ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट दायर की थी.

भाजपा के मंत्रिमंडल पर टिप्पणी: श्रीमान भूपेश बताए उन्होंने अपने सीनियर सिहदेव का अपमान क्यों किया : रंजना साहू

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भाजपा के मंत्रिमंडल पर टिप्पणी करने के बाद भाजपा की पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता रंजन साहू ने तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया है सीनियर जूनियर की बात करने वाले भूपेश बघेल जी बताएं कि उन्होंने श्री टी एस सिंहदेव का अपमान बार-बार क्यों किया। रंजना ने कहा कि अगर सीनियर जूनियर की चिंता भूपेश बघेल ने अपने मुख्यमंत्री रहते की होती तो आज उन्हें शायद इतनी बुरी हार का सामना न करना पड़ता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि यह समय कांग्रेस के लिए आत्म मंथन का है परंतु आज भी कांग्रेस बेवजह की टीका टिप्पणियों में अपना समय जाया कर रही है यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आगे भी कांग्रेस का भविष्य अंधकार मय होगा। भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि उनके पदाधिकारी जो गंभीर आरोप अपने प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी पर लगा रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के कार्यकाल पर लगा रहे हैं उसका क्या जवाब है कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार रहते छत्तीसगढ़ दिल्ली वालों के लिए अय्याशी का अड्डा बन गया था भूपेश बघेल जी का इस पर क्या कहना है? भूपेश बघेल जी के करीबी माने जाने वाले बृहस्पति सिंह लगातार कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता श्री सिंहदेव का अपमान करते रहे, उन पर झूठे आरोप तक लगाए.

चार डाक्टरों की गिरफ्तारी का आईएमए ने किया विरोध

रायपुर। बिलासपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार को चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किये जाने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है और कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट का सही तरीके से अवलोकन न कर पुलिस ने जो कार्रवाई की वह गलत है। बैठक में सदस्य डाक्टरों ने बिलासपुर के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट्स का अवलोकन किया। इस रिपोर्ट में सिम्स बिलासपुर की संदर्भित विशेषज्ञों की उपस्थिति के बगैर जांच रिपोर्ट को संज्ञान में न लेकर पुलिस प्रशासन ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया जिसका आई एम ए रायपुर और हॉस्पिटल बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। 29 वर्षीय गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा की मृत्यु को लेकर गठित की गई जांच समिति ने 25 मई को अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया था कि मरीज को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था और उसे उचित उपचार दिया गया था। उसके इलाज में किसी चिकित्सकीय लापरवाही का कोई स्पष्ट सबूत मौजूद नहीं है। जांच समिति ने कहा हालाँकि, अज्ञात विषाक्तता के संदेह के मद्देनजर, धुलाई के संग्रह का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जिससे गंभीर रोगी के कम समय तक अस्पताल में रहने के कारण सटीक निदान और मृत्यु के कारण पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

डोमिनोज का फेंचायजी दिलाने 25 लाख 77 की ठगी करने वाले बिहार के दो गिरफ्तार

रायपुर। डोमिनोज का फेंचायजी दिलाने के नाम पर 25 लाख 77 हजार 500 रुपये की ठगी करने वाले बिहार के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने देश भर में फेंचायजी दिलाने सहित अलग अलग तरीको से लोगों को अपने झांसे में लेकर राजधानी रायपुर के एक शख्स के साथ ठगी की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाईल, 9 ए.टी.एम. कार्ड, फिंगर प्रिंट स्केनर, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड एवं पासपोर्ट को जब्त किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोषी नगर निवासी सुदिप्ता धारा को 9 अक्टूबर को उसके पास मोबाईल 8981136219 से फोन आया था। उसने अपना नाम अभिषेक मण्डल नोएडा का रहने वाला बताया। कहा कि आपने डोमिनोज फें चाईजी के लिए अप्लाई किया था, जिस पर सुदिप्ता उसकी बातों आ गई। आरोपी ने डोमिनोज फें चाईजी दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग बहाने से पैसों की मांग कर अपने बैंक खातों में कुल 25,77,500 रूपए जमा करा लिए। जिसके बाद सुदिप्ता के पास कोई भी मेसेज नहीं आया। इस पर ठगी होने के शक में टिकरापारा थाना जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर खाईवालों ने युवकों को महादेव सट्टा एप के काम में लगाया

दुर्ग. महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ चन्द्राकर को पुलिस और ईडी की टीम दुबई में तलाश रही है. लेकिन दुर्ग जिले में अब भी महादेव सट्टा एप के खाईवालों का कारोबार जारी है. दरअसल, महादेव सट्टा एप के खाइवालों की दबंगई का एक वीडियो शोसल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सट्टा खाईवाल जय शर्मा और उसके पिता विक्की शर्मा, साथी बलवीर सिंह तीन युवकों को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर रहे हैं. अब इस मामले की शिकायत दुर्ग के छावनी सीएसपी और एसपी रामगोपाल गर्ग से युवकों ने की है. जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. इस वायरल वीडियो में तीन लड़कों को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं. इसमें से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए विक्की शर्मा के हाथों में प्लास्टिक का डंडा नजर आ रहा है. वहीं दूसरा युवक बलबीर सिंह युवकों को पीट रहा है. इसके अलावा विक्की शर्मा अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहा है. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विक्की शर्मा का बेटा जय शर्मा है. जय शर्मा डंडे से इस तरह युवकों को पीट रहा है, जैसे पुलिस अपराधियों को थर्ड डिग्री देती है.

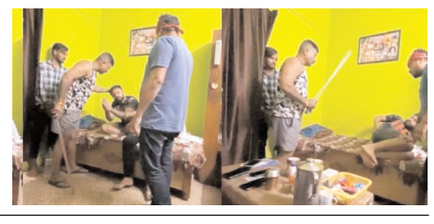

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में हुए शामिल

वास्तविक शिक्षा वह जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ-साथ चरित्रवान भी : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज सरस्वती शिक्षण संस्थान रोहणीपुरम् में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभावान् छात्रा-छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना अथवा डिग्रियां हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ-साथ चरित्रवान भी बनाएं, उसे राष्ट्र के लिए उज्ज्वल चरित्र के नागरिक तैयार करें। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि हम सभी सनातन जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। इन मूल्यों को बचाए रखना ही पूरी दुनिया को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। इस समय पूरे विश्व की परिस्थितियों को देख हम रहे है, महसूस भी कर रहे हैं। हर तरफ मनुष्य और मानवता पर संकट दिखता

है। आपसी संघर्षों में उलझी दुनिया बार-बार भारत की ओर देखती है, क्योंकि हम विश्व शांति और वसुधैव कुटुबंकम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत विश्व गुरू बनेगा, दुनिया को शांति-एकजुटता और समन्वित विकास की ओर भारत ही लेकर जाएगा। यह समय भारत का स्वर्णिम समय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कहना है कि शिक्षा ही है जो देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरस्वती शिक्षण संस्थान पूरे देश में एक ऐसी शिक्षा प्रदान कर रही है, जिससे देश में विद्यार्थी को सम्पूर्ण मनुष्य के रूप में तैयार कर सकें। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य शिक्षा पद्धति बौद्धिक रूप से बच्चों को को तैयार करती है, मगर सरस्वती शिक्षण संस्थान बच्चों को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के उत्थान अर्थात आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरस्वती शिक्षण संस्थान पूरे देश में ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर रही है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, हुड़दंगियों और नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं

रायपुर। नव वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा रायपुर के प्रमुख होटल, फार्म हाऊस, पार्क, चौक, चौराहों एवं भीड़-भाड़ सहित अन्य स्थानों में आयोजित कार्यक्रम सहित अपराधियों एवं अपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के मद्देनजर कानून व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर

रायपुर पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम कर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. प्रभारी पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व व समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारियों सहित सैकड़ो पुलिसकर्मियों को डियूटी में तैनात किया गया है. शहर के 16 अलग-अलग स्थानों आमानाका ओव्हरब्रिज चौक, (अशोका बिरयानी के पास), सरस्वती थाना के सामने, आमापारा चौक, गोल चौक, डीडी नगर, जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, एसआरपी चौक, मरीन ड्राईव तालाब, पुराना बस स्टैण्ड, फाफाडीह चौक, रेल्वे स्टेशन के सामने, भारत माता चौक गुढ़ियारी, भनपुरी तिराहा, बंजारी मंदिर चौक, सिंधानिया चौक उरला एवं बुधवारी बाजार चौक उरला में फिक्स पिकेट्स लगाया गया है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.